



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2023 ई0 (फाल्गुन 06, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-08

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	193-234	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	39-41	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	03-04	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	201-224	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4

## विज्ञप्ति/नियुक्ति

05 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 2632/XXX(4)/2023-04(1)/2018-मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2022 में उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2016 के नियम-18 एवं नियम-20 के प्रावधानानुसार चयनित तथा प्रोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति/पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु, महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-5720/UHC/Admin.A/2022, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित 02 अधिकारियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा, वेतनमान ₹ 144840-194660(J-5), (समतुल्य ग्रेड वेतन- ₹ 8900) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1.	श्री मुकेश चन्द्र आर्य	चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	पदोन्नति कोटा
2.	श्री मन्जु सिंह मुंडे	चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट, बागेश्वर	पदोन्नति कोटा

2- उक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं।

3- उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

## वित्त अनुभाग-8

## विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 89480/2023/08(100)/XXVII(8)/2018-उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक आयुक्त सुश्री नेहा मिश्रा को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत उपायुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल-'11' ₹0 67700-208700 (पूर्व वेतनमान ₹0 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹0 6600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नत अधिकारी को उपायुक्त के पद पर निम्नानुसार तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1.	सुश्री नेहा मिश्रा	उपायुक्त, (ऑडिट) मुख्यालय, देहरादून

3-उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए, योगदान आख्या की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4-पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।



अधिसूचना/स्थानान्तरण

09 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 17/2022/04(100)/XXVII(8)/2019-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-5418/आयुक्त रा0क0 उत्तरा0/स्था0अनु0/रा0कर/2022-23/दे0दून, दि0 07.12.2022 के द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय/संस्तुति के क्रम में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सचलदल इकाईयों के सापेक्ष निम्नलिखित सहायक आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सहायक आयुक्त-सचलदल इकाई

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान/ कार्यालय	नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री नितिन कुमार विश्वकर्मा, सहायक आयुक्त	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, देहरादून	सचलदल, भगवानपुर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 27 में प्राप्त विचलन के आधार पर
2.	श्री मो0 जिशान मलिक, सहायक आयुक्त	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, हल्द्वानी	सचलदल, रुद्रपुर	उक्तानुसार
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, हल्द्वानी	सचलदल, किच्छा	उक्तानुसार
4.	श्री दिनेश कुमार मिश्रा, सहायक आयुक्त	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, रुड़की	सचलदल, हल्द्वानी	उक्तानुसार
5.	श्री दुबे उमेश महेन्द्रनाथ, सहायक आयुक्त	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, देहरादून	सचलदल, विकासनगर	उक्तानुसार
6.	श्री संतोष कुमार, सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त, राज्य कर, पिथौरागढ़	सचलदल, काशीपुर	उक्तानुसार
7.	डॉ. कुलदीप सिंह, सहायक आयुक्त	अपर आयुक्त (ऑडिट विंग), राज्य कर, देहरादून	सचलदल, आशारोड़ी	उक्तानुसार
8.	श्री विनोद कुमार आर्य, सहायक आयुक्त	संयुक्त आयुक्त (रिस्क मैनेजमेन्ट एवं डाटा एनालिसिस), राज्य कर, देहरादून	सचलदल, हरिद्वार	उक्तानुसार
9.	श्री टीका राम चन्पाल, सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून	सचलदल, कोटद्वार	उक्तानुसार
10.	श्री अनिल कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3, रुद्रपुर	सचलदल, खटीमा	उक्तानुसार
11.	श्री अंजनी कुमार सिंह, सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, ऋषिकेश	सचलदल, रुड़की	उक्तानुसार

स्थानान्तरण-सहायक आयुक्त, सचलदल इकाई से अन्य कार्यालय

क्र सं	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान/कार्यालय	नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री धर्मवीर सिंह, सहायक आयुक्त	सचलदल, विकासनगर	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, ऋषिकेश	धारा-27 में प्राप्त विचलन के आधार पर
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, सहायक आयुक्त	सचलदल, हरिद्वार	सहायक आयुक्त, राज्य कर, पिथौरागढ़	उक्तानुसार
3.	श्री मो0 कासिम, सहायक आयुक्त	सचलदल, हल्द्वानी	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3, रुद्रपुर	उक्तानुसार
4.	श्री अमित कुमार, सहायक आयुक्त	सचलदल, आशारोड़ी	सहायक आयुक्त, राज्य कर, आडिट, देहरादून	उक्तानुसार
5.	श्री मो0 इमरान, सहायक आयुक्त	सचलदल, किच्छा	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, विकासनगर	उक्तानुसार
6.	श्री अविनाश दीपक, सहायक आयुक्त	सचलदल, काशीपुर	उपायुक्त (ऑडिट), राज्य कर, देहरादून	उक्तानुसार
7.	श्री चंचल सिंह चौहान, सहायक आयुक्त	सचलदल, कोटद्वार	सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3, हरिद्वार	उक्तानुसार
8.	श्री प्रदीप चन्द्र, सहायक आयुक्त	सचलदल, खटीमा	सहायक आयुक्त, राज्य कर, अल्मोड़ा	उक्तानुसार
9.	डॉ. हरिओम वर्मा, सहायक आयुक्त	सचलदल, रुद्रपुर	सहायक आयुक्त, राज्य कर, किच्छा	उक्तानुसार

02- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन/आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,  
दिलीप जावलकर,  
सचिव।

वित्त अनुभाग-9विज्ञप्ति/तैनाती

10 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 574/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2008-उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-384/2022/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2022 के द्वारा पदोन्नत श्री अतुल कुमार शर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय देहरादून के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2-श्री शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना ही तत्काल अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिलीप जावलकर,  
सचिव।



## खेलकूद अनुभाग

## अधिसूचना

10 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 832/VI-3/2023-30(11)/2022-राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, आधारभूत खेल सुविधायें विकसित करने, खेलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हुए उनको रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अन्य खेलों की तरह "मलखम्ब" खेल को भी शासन की अधिसूचना संख्या-938/VI-3/2021-33(07)/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित "खेल नीति-2021" में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,  
सचिव।

## वित्त अनुभाग-8

## शुद्धि-पत्र

20 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 92861/2023/08(100)/XXVII(8)/2018-इस कार्यालय के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या-89480/2023/08(100)/XXVII(8)/2018, दिनांक 09 जनवरी, 2023 द्वारा राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक आयुक्त सुश्री नेहा मिश्रा को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उपायुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल-'11' रु० 67700-208700 (पूर्व वेतनमान रु० 15600-39100, ग्रेड वेतन रु० 6600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उपायुक्त, (ऑडिट) मुख्यालय, देहरादून के पद पर तैनाती प्रदान की गयी थी।

2-इस सम्बन्ध में उक्त आदेश के प्रस्तर-02 में उल्लिखित सुश्री नेहा मिश्रा, नव पदोन्नत उपायुक्त के नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय "उपायुक्त, (ऑडिट) मुख्यालय, देहरादून" के स्थान पर "उपायुक्त, ऑडिट विंग, कार्यालय-अपर आयुक्त (ऑडिट विंग) देहरादून" पढ़ा व समझा जाये।

3-उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये; शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

दिलीप जावलकर,  
सचिव।

## औद्योगिक विकास अनुभाग-2

### कार्यालय ज्ञाप

31 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 85/ई०प०-28344/VII-A-2/2023/02(4)/2022-राज्यपाल, राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नवीन और विद्यमान उद्योगों को अपना समर्थन प्रदान करना, मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, विद्यमान लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, लॉजिस्टिक्स सूचकांक में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाना तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023" बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

### "उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023"

1.

#### प्रस्तावना

हिमालयी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अवस्थित उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य के उत्तर में चीन (तिब्बत), पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ अंतर-राज्यीय सीमाएँ लगी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप होने के कारण राज्य को महत्वपूर्ण बाजार में पहुंच के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता भी सुगमता से होती है। राज्य में जैविक कृषि उत्पादों, कृषि आधारित एवं प्रसंस्कृत भोजन, संगंध एवं औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा पर्यटन एवं वेलनेस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात की असीम सम्भावनाएँ हैं।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड के नये राज्य के रूप में गठन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2003 में स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में तीव्र गति से औद्योगीकरण हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० का गठन कर राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं युक्त एकीकृत औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में विश्व तथा देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों द्वारा अपनी विनिर्माणक इकाइयों की स्थापना यहां पर की गयी। राज्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता से औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति



प्रख्यापित कर निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है। उद्योगों के अनुकूल नीतियों एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण ने उत्तराखण्ड को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित किया है।

राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत 5 वर्षों में 9.48 प्रतिशत की दर से (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) रेट (सीएजीआर) वर्ष 2015-16 के बीच रु. 1,77,163 से बढ़कर रु. 2,53,666 हो गया था। वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 4.2 प्रतिशत ह्रास हुआ है, भविष्य में जिसके वर्ष रु. 2,43,012.3 लाख से बढ़कर रु. 2,78,006 लाख तक होने की सम्भावना है। उत्तराखण्ड में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले दो वर्षों में (दिसम्बर, 2019 – दिसम्बर, 2021 तक) रु. 80.7 करोड़ से बढ़कर 10 गुना, यथा रु. 918 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 के दौरान, उत्तराखण्ड से निर्यात में भारतवर्ष की सगावेशी नकारात्मक विकास दर 0.91 प्रतिशत आंकी गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य में 6.38 प्रतिशत (2.14 बिलियन अमरीकी डॉलर) की (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्ज की गयी है।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा कारोबार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2019-20 के तहत विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तराखण्ड भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है।

अगस्त, 2020 में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2020 रिपोर्ट में, उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में अभिज्ञात किया गया है। यह बुनियादी निर्यात सुविधाओं एवं अवसंरचना, एक अनुकूल व्यापार और निर्यात वातावरण के साथ-साथ राज्य द्वारा अच्छे निर्यात प्रदर्शन की उपस्थिति से संभव हुआ है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में राज्य ने हिमालयी राज्यों में अपना प्रथम स्थान बनाये रखा है।

मार्च, 2021 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इण्डेक्स में उत्तराखण्ड को 13वें स्थान पर रखा है। राज्य के लैण्डलॉक्ड स्टेट होने के कारण, राज्य के निर्यातकों को अन्य राज्यों की अपेक्षा एक अंतर्निहित प्रतिकूल लागत वहन करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कच्चे माल को अपने परिसर में लाने के साथ-साथ तैयार उत्पादों के नौ-परिवहन में उच्च लॉजिस्टिक्स लागतें वहन करनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, उत्तराखण्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग

रु. 15,915.54 करोड़ की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया है।

राज्य सरकार का यह विश्वास है कि राज्य में स्थायी व सतत् औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के विकास से राज्य में न केवल विनिर्माण एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी वृद्धि होगी। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य की सामरिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु अधिकतम लाभ उठाने के आशय से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 को प्राख्यापित करने का निर्णय लिया है। यह नीति लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नए और मौजूदा उद्योगों को अपना समर्थन देने के इरादे से प्रख्यापित की जा रही है और इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों का सृजन, लॉजिस्टिक्स सूचकांक (LEADS) में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाना तथा वित्तीय व गैर-वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है।

## 2. परिभाषाएं

इस नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क तथा अन्य लॉजिस्टिक्स इकाइयों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

- (क) "लॉजिस्टिक्स" से लॉजिस्टिक्स प्रबन्धन की वह समग्र प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए संग्रहीत कर उन्हें अन्तिम गंतव्य तक पहुंचाता है;
- (ख) "लॉजिस्टिक्स सेवाओं" से कार्गो एकीकरण/पृथक्करण, वितरण, सामग्री और कंटेनर के इंटरमॉडल हस्तांतरण, खुले और बंद भंडारण, कार्गो पारगमन अवधि में भंडारण के लिए उपयुक्त स्थिति, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, और व्यापार और वाणिज्यिक सुविधाएं और सामान्य सुविधाएं अभिप्रेत हैं;
- (ग) "इको-लॉजिस्टिक्स या ग्रीन लॉजिस्टिक्स" से ऐसी तकनीकें अभिप्रेत हैं, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान तकनीक, बायो-डिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना शामिल है;



- (घ) "सहायक बुनियादी ढांचे" से लॉजिस्टिक्स पार्क की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक सड़कों, संचार सुविधाओं, खुले और हरे भरे स्थानों, पानी की पाइपलाइन, सीवेज/जल निकासी तथा निपटान की सुविधा, विद्युत लाइन, फीडर, सौर पैनल्स और अन्य सुविधाओं के विकास अभिप्रेत है;
- (ङ0) "अंतर्देशीय कंटेनर डिपो" से एक ऑफ सी-पोर्ट सुविधा अभिप्रेत है, जिसमें एक निश्चित स्थिर अधिष्ठापन या अन्यथा, उपकरण, मशीनरी इत्यादि सेवाओं के संचालन हेतु सेवायें उपलब्ध कराने तथा/या लेडन इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट कण्टेनर्स के कस्टम बॉण्डेड या नॉन बॉण्डेड कार्गो से भंडारण की सुविधा सहित सीमा शुल्क नियंत्रण से अनुज्ञापन की सुविधा हो। इन सुविधाओं में सड़क संयोजन, रेल संयोजन, सीमा शुल्क/नॉन कस्टम बॉण्डेड वेयरहाउसिंग, ट्रक टर्मिनल्स आदि तथा अन्य उपयोग की सामान्य सुविधाएं, जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं, सम्मिलित हैं। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जिसमें न्यूनतम रु. 50 करोड़ का निवेश किया गया हो और न्यूनतम क्षेत्रफल 18 एकड़ हो;
- (च) "एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स" से राज्य की एयर कार्गो मूवमेंट क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई सुविधाएं अभिप्रेत हैं। ये सुविधाएं एयरपोर्ट/ऑफ-एयरपोर्ट स्थानों के भीतर स्थित हो सकती हैं और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ हैंडलिंग, स्टोरेज और कार्गो की निकासी जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं;
- (छ) "वेयरहाउस" से किसी भी कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित एक खुला/बंद क्षेत्र, जहां वेयरहाउस कार्गो के संचालन और भंडारण के लिए थोक/ब्रेकबल्क रूप में सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, अभिप्रेत हैं। पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में न्यूनतम रु. 2.5 करोड़ के निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्र में गोदाम की सुविधा और गैर-पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी-डी) में न्यूनतम रु. 5 करोड़ निवेश के साथ 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र आवश्यक होगा।
- (ज) "कोल्ड चेन सुविधा" से कृषि, बागवानी, डेयरी, मछली और समुद्री, पोल्ट्री और मांस उत्पादों, फार्मा आदि जैसे खराब होने वाले/तापमान के प्रति संवेदनशील कार्गो के भंडारण और न्यूनतम प्रसंस्करण के लिए एक सुविधा जो स्रोत से उपभोक्ता तक जुड़ी हुई है, अभिप्रेत है। रु. 5 करोड़ के निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट में कोल्ड चेन सुविधा:

कोल्ड चेन सुविधाओं के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:—



- (एक) नियंत्रित वातावरण/संशोधित वायुमंडल कक्ष, परिवर्तनीय आर्द्रता कक्ष, व्यापक भंडारण, इण्डिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग, आदि।
- (दो) मिनिमल प्रोसेसिंग सेंटर में वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, सफाई, वैक्सिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग, फॉग ट्रीटमेंट, विकिरण आदि की सुविधा।
- (तीन) शुरु से अन्त तक गोबाइल प्री-कूलिंग वैन और रीफर ट्रक युक्त एक समर्पित कोल्ड चेन सुविधा।
- (अ) "ट्रक टर्मिनलों" से ऐसी सुविधाएं अभिप्रेत हैं, जो रणनीतिक स्थानों जैसे कि जिला लॉजिस्टिक्स नोड्स, औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे चौराहे आदि पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए विकसित की जाती हैं। ट्रक टर्मिनल ट्रकों की मरम्मत और रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स के लिए स्टोर, एटीएम, ईंधन स्टेशन, पार्किंग स्थान, परिवहन कार्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, वेटब्रिज आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ कार्गो के लोडिंग/अनलोडिंग (क्रॉस-डॉकिंग) की सुविधा के साथ-साथ चालकों और उनके सहायकों के लिए ठहरने की सुविधा हो सकती है। ट्रक टर्मिनलों पर वाहन की फिटनेस स्वचालित रूप से जांचने की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। ट्रक टर्मिनल, जिसमें रु. 5 करोड़ का निवेश हो और न्यूनतम 45,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल हो (यह हब/स्पोक/लॉजिस्टिक पार्क का हिस्सा होना चाहिए)।
- (अ) "लॉजिस्टिक्स पार्क" से ऐसी सुविधाएं अभिप्रेत हैं, जो कार्गो एकीकरण/अलगाव, वितरण, कार्गो और कंटेनरों के आंतरिक-मोडल स्थानांतरण, खुला और/या बंद भंडारण, तापमान नियंत्रित और/या परिवेश भंडारण, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, पार्किंग, अर्द्ध-निर्मित या तैयार माल के कुशल संचलन और वितरण के लिए आवश्यकता के अनुसार मूल्यवर्द्धित सेवाएं और अन्य संबंधित सुविधायें/सेवाएं प्रदान करती हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क आंतरिक सड़कों, संचार सुविधाओं, खुले और हरे भरे स्थानों, पानी की पाइपलाइनों, सीवेज और ड्रेनेज लाइनों, विद्युत लाइनों, फीडर और पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सुविधाओं सहित सहायक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे।
- (द) "ट्रांसपोर्ट/ट्रक मालिक/फ्लीट ऑपरेटर्स/एग्रीगेटर्स" से कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन (एक्स-शोरूम कीमत जो लागू हो) क्रय किये गये हों अभिप्रेत हैं। ट्रकों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जायेगा:-



- (एक) बड़ा ट्रक: {32-40 फीट, 14-व्हीलर ट्रक (21 टन से 31 टन क्षमता)}
- (दो) मध्यम ट्रक: {24-32 फीट, 12-व्हीलर ट्रक (16 टन से 25 टन क्षमता)}
- (तीन) छोटा/मिनी पिकअप ट्रक: {20-32 फीट, 10-व्हीलर ट्रक (10 टन से 15 टन क्षमता)}
- (ग) "विस्तार" से विद्यमान इकाई/परियोजना की स्थिर परिसम्पत्तियों, यथा: संयंत्र व मशीनरी तथा फैक्ट्री भवन (विद्यमान इकाई के कार्यशील पूंजी तथा भूमि की लागत को छोड़कर) में विद्यमान स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, जिससे इकाई की विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की अभिवृद्धि हो अभिप्रेत है।
- (ङ) "परियोजना लागत" से नई इकाई/परियोजना के लिए भूमि में किये गये पूंजी निवेश, एक लॉजिस्टिक्स इकाई के लिए निर्मित सुपर बिल्ट-अप एरिया, संयंत्र व मशीनरी तथा कारखाना भवन, (कार्यशील पूंजी तथा भूमि की लागत को छोड़कर) में किये गये पूंजी निवेश अभिप्रेत है। प्रोत्साहनों की गणना के लिए सर्किल रेट के आधार पर भूमि के कुल मूल्य का 25 प्रतिशत या भूमि की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, को ही हिसाब में लिया जाएगा।
- 'सुपर बिल्ट-अप एरिया को बिल्ट-अप एरिया के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है और वह स्थान जो सामान्य क्षेत्रों जैसे सीढ़ी, लॉबी, एलेवेटर, क्लब हाउस, शाफ्ट आदि द्वारा आच्छादित हो। सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र को "बिक्री योग्य क्षेत्र" के रूप में भी जाना जाता है, जिसके आधार पर डेवलपर्स आमतौर पर अंतिम शुल्क प्रभार्य करते हैं।'
- (च) "हब और स्पोक नेटवर्क" से एक केन्द्रीकृत, एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रणाली अभिप्रेत है, जिसे लागत कम रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हब और स्पोक वितरण केन्द्र कई अलग-अलग मूल उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद प्राप्त कर, उन्हें समेकित करते हुए सीधे गन्तव्यों पर भेजते हैं।

### 3. पात्रता

- (i) एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और किसी भी अन्य कानूनी इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत संस्था/संस्थान इस नीति के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

- (ii) केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडल की परियोजनाओं को भी नीति में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।
- (iii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की इकाइयाँ, जो किसी अन्य नीति के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, वे इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ समेकित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
- (iv) प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में विद्यमान औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण की दी गयी परिभाषा के अनुरूप विद्यमान इकाई के मौजूदा पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश किया जाना आवश्यक होगा।
- (v) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई ही नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगी।
- (vi) उत्तराखण्ड आधारित माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) पर जारी बीजक (इनवॉयस) में उल्लिखित धनराशि को ही प्रोत्साहनों सहायता के लिए गणना में लिया जाएगा।

#### 4. दृष्टि

- (i) उत्तराखण्ड में एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा और विकास से नवाचार, कुशल जनशक्ति, गुणवत्ता और विघटनकारी प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता, परिचालन दक्षता और स्थिरता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने के साथ-साथ उत्तराखण्ड में व्यापार और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- (ii) इस नीति का उद्देश्य उत्तराखण्ड में पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की क्रॉस-फंक्शनल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। यह लॉजिस्टिक्स इनेबलर्स, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं को बढ़ाने और बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। राज्य के भीतर हब-स्पोक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इस नीति के आलेख को तैयार किया गया है।

#### 5. नीति के उद्देश्य

- (i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक सरलीकृत, सक्रिय और उत्तरदायी संस्थागत तंत्र का निर्माण।



- (ii) गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं/क्लस्टरों से रेल-सड़क कनेक्टिविटी आदि जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण—
- (iii) राज्य को एक हब-स्पोक लॉजिस्टिक्स मॉडल के रूप में प्रतिस्थापित करना, जिससे पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत हों तथा लॉजिस्टिक्स के लिए संपूर्ण व्यावसायिक मूल्य श्रृंखला में लाभ सृजित हो सके।
- (iv) राज्य में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हरित और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- (v) फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- (vi) आर्थिक गतिविधियों तथा बृहद स्तर पर रोजगार प्रोत्साहन हेतु विद्यमान वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण तथा सुधार।
- (vii) मौजूदा और नए लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।
- (viii) लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने से जुड़ी सभी राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय।
- (ix) ग्रीन एवं इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करना।

#### 6. रणनीति

- (i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक सरलीकृत, सक्रिय और उत्तरदायी संस्थागत तंत्र का निर्माण।
- (क) अन्तःक्षेप/सुधार एवं विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य भर में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का मानचित्रण।
- (ख) राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, सेवाओं, सड़क व रेल नेटवर्क के प्रस्तावित विकास की क्षमता और परिचालन बाधाओं की पहचान।
- (ग) रेल नेटवर्क, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं जैसे लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन।
- (घ) एमएसएमई नीति, 2015, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रख्यापित इसी प्रकार की अन्य नीति के केन्द्रित क्षेत्रों पर विचार।

- ii. गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं/क्लस्टरों से रेल-सड़क कनेक्टिविटी आदि जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण।

इस नीति का उद्देश्य मौजूदा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के उपयोग में सुधार करना है, जो निजी विकासकर्ता या विभिन्न राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों के नियंत्रण में हैं। प्रासंगिक हितधारक परामर्श के माध्यम से उनके उपयोग में सुधार के लिए मौजूदा सुविधाओं का मूल्यांकन विभिन्न प्रदर्शन मानकों के आधार पर किया जाएगा।

- iii. राज्य में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हरित और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देना।

(क) उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण के अनुकूल व सतत लॉजिस्टिक्स तथा परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है। ग्रीन लॉजिस्टिक्स ऐसी तकनीक हैं, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान तकनीक, बायो-डिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाना, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना आदि शामिल हैं। इस प्रकार, इस नीति के तहत हरित लॉजिस्टिक्स पहल को बढ़ावा देने के साथ-साथ मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स पार्कों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) राज्य चेकपॉइंट के माध्यम से कार्गो की कुशल आवाजाही के लिए स्मार्ट सिस्टम लागू करेगा। एक्जिम/डिफेंस कार्गो ले जाने वाले वाहनों के लिए "ग्रीन चैनल्स" की पहचान की जाएगी।

- iv. राज्य में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

(क) उत्तराखण्ड सरकार राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

(ख) भण्डारण और संचालन सुविधाओं का विकास: यह नीति फार्मास्यूटिकल्स, ई-कॉमर्स, कृषि उत्पादों आदि जैसे फोकस क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स क्षमता के सुधार के लिए रणनीतिक नोड्स पर भण्डारण और हैंडलिंग सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है।



- (ग) रणनीतिक स्थानों पर एयर फ्रेट स्टेशनों तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का विकास: इस नीति में एयर कार्गो क्षमता, वर्तमान क्षमता बाधाओं, हवाई संपर्क आदि का आंकलन किया जाएगा। तदनुसार, एयर कार्गो को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की मैपिंग करते समय एयर कार्गो टर्मिनलों और एयर फ्रेट स्टेशनों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (घ) ई-कॉमर्स का समर्थित विकास: यह नीति उच्च गति वाले क्षेत्रों में, मांग स्थानों के समीप तथा शहरों की परिधि के आसपास ई-कॉमर्स हब के विकास को बढ़ावा देती है। यह ई-कॉमर्स क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शहरों में यातायात भी संकुलित करेगा।
- (ङ) ट्रक टर्मिनल, चालक विश्राम क्षेत्र एवं पार्किंग स्थलों का विकास: नीति का उद्देश्य औद्योगिक पार्कों तथा उच्च कार्गो घनत्व की परिधि के आसपास रणनीतिक स्थानों (राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे चौराहे आदि) पर ट्रक टर्मिनलों की मरम्मत एवं रखरखाव, चालक विश्राम क्षेत्र और पार्किंग स्थानों के विकास को बढ़ावा देना है। यह भीड़भाड़ को कम करेगा और ट्रकों के शहर में प्रतिबन्धित समय के दौरान उचित प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करेगा।
- v. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स कंपनियों को क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

उत्तराखण्ड सरकार क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक कंपनियों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह नीति उत्तराखण्ड में क्षेत्र की क्षमता में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है। इस उद्देश्य के लिए अपनाई जा सकने वाली प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- (क) सामग्री से निपटने, कार्गो परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर कार्गो यातायात को कम करने में रोबोटिक्स और स्वचालन।
- (ख) लेन-देन के सत्यापन के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियाँ और सुरक्षित तरीके से दस्तावेजीकरण और सूचनाओं का आदान-प्रदान।
- (ग) सिमुलेशन के निर्माण और लेआउट और नई मशीनरी आदि में नए प्रयोगों के प्रभाव को जोखिम मुक्त तरीके से मापने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक। यह तकनीक आवर्ती प्रवृत्तियों की पहचान करती है और परिचालन वातावरण में संभावित कमजोरियों को दर्शाती है, जो भविष्य में सुधार के लिए इनपुट प्रदान करती है।



(घ) उन्नत मांग नियोजन, रूट प्लानिंग, संचालन योजना आदि के लिए कृत्रिम और ऑगमेंटेड इण्टेलिजेंस टूल्स के उपयोग से समयावधि, मानवीय त्रुटियों और लागत में कमी आई है। कृत्रिम इण्टेलिजेंस (एआई) आधारित प्रौद्योगिकियां कम कार्बन उत्सर्जन के लिए सर्वोत्तम मार्ग विकल्प भी प्रदान करती हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पहल का समर्थन होता है।

(ङ) नीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्ट-अप और अन्य व्यावसायिक इकाइयों द्वारा तकनीकी पेटेंट रजिस्ट्रीकरण को प्रोत्साहित करके और/या नीति अवधि के दौरान विशेष प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करके लॉजिस्टिक्स में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और नवीन समाधानों के लिए वार्षिक पुरस्कार/पुरस्कार भी प्रारम्भ किए जाएंगे।

टिप्पणी: विशेष महत्त्व की बृहद परियोजनाओं (नई प्रौद्योगिकी आधारित) का केस-टू-केस बेसिस पर अनुकूलित पैकेज स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति प्रोत्साहन के अनुकूलित पैकेज की सिफारिश करेगी।

vi. राज्य के मौजूदा और नए लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को सहायता प्रदान करना (ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक्स)

सतत चल रहे व्यावसायिक सुधारों के एक भाग के रूप में और संबंधित विभागों से वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, मौजूदा लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनुमोदन प्रदान करने में शामिल मौजूदा प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना है। एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पहले से मौजूद है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान, ट्रेकिंग, अनुमोदन आदि के लिए इसे मजबूत किया जाएगा, जो भौतिक सत्यापन की आवश्यकता वाले सभी स्तरों में भौतिक स्पर्श बिंदुओं को हटा देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन को समय सीमा के भीतर स्वीकृत किया जाता है, उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

vii. लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने से जुड़ी सभी राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

राज्य सरकार संभावित निर्यात बाजारों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह विदेशों के दूतावास कार्यालयों में व्यापार केंद्रों के साथ गठजोड़ करके निर्यात



प्रोत्साहन डेस्क के साथ संबंध स्थापित करेगा।

राज्य में लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, सरकार निर्यात योजना (टीआईईएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि के लिए व्यापार अवसंरचना (ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर) जैसी योजनाओं का लाभ उठाएगी।

राज्य सरकार मौजूदा लॉजिस्टिक्स और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और राज्य में प्रासंगिक निर्यात परिषदों के शिविर कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रासंगिक लॉजिस्टिक्स और अन्य निर्यात संवर्धन संगठनों जैसे फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड (IIFT), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC), सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SEPC), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी कॉर्पोरेशन (ECGC), चाय बोर्ड आदि के साथ भी सहयोग करेगी।

- viii. उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक योजना का विकास एवं क्रियान्वयन करना है।

उत्तराखण्ड सरकार लॉजिस्टिक के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ एक व्यापक लॉजिस्टिक योजना का विकास और कार्यान्वयन करेगी:

- (क) **चालक सशक्तिकरण और रोजगार:** राजमार्गों तथा प्रमुख सड़कों के साथ ट्रकों और उनके चालकों के लिए समर्पित पार्किंग तथा विश्राम स्थलों का चिन्हांकन।
- (1) प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए योजनाएं।
  - (2) बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्य के राजमार्गों में प्राथमिक सुविधा प्रदान करने वाली सुविधाओं/केंद्रों का विकास।
  - (3) चालकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं का संचालन।
  - (4) राज्य कौशल मिशन द्वारा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- (ख) **वेयरहाउसिंग:** भूमि की सुगम उपलब्धता और भूमि उपयोग के रूपांतरण के लिए सुविधाजनक वातावरण, वेयरहाउसिंग के लिए एफएआर में छूट, गोदामों की ऊंचाई आदि के संबंध में मानकों का निर्धारण।
- (1) एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अधीन गोदामों की स्थापना और संचालन के लिए अनुज्ञा तथा अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था।
  - (2) राज्य में गोदामों की ई-डायरेक्टरी तैयार करना।

(ग) स्मार्ट एनफोर्समेंट: न्यूनतम निरीक्षण और सड़क पर ट्रकों के रुकने हेतु ईको-सिस्टम विकसित करना। ट्रक आवाजाही चौकियों की पहचान कर आ रही बाधाओं को दूर करना तथा माल की दुलाई हेतु सड़क अधिनियम, 2007 एवं भारतीय मोटर वाहन अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।

- (1) सड़क प्रवर्तन के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- (2) प्रोद्युडिंग कार्गो को संबोधित करने की पहल।
- (3) प्रवर्तन की एक वैकल्पिक/नवीन पद्धति को अपनाने के लिए रोड़मैप तैयार करना।
- (4) दूरस्थ प्रवर्तन के लिए वाईफाई/सीसीटीवी/डब्ल्यूआइएम का प्रावधान।
- (5) जीएसटीएन/फास्टैग/वाहन/सारथी डेटाबेस का एकीकरण और स्मार्ट प्रवर्तन में उपयोग।

(घ) सिटी लॉजिस्टिक्स: शहरों के पास पेरी-शहरी क्षेत्रों में ट्रक पार्किंग/वेयरहाउसिंग के साथ लॉजिस्टिक्स पार्क/ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था।

- (1) शहर की सीमाओं के भीतर लास्ट माइल डिलीवरी के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे और यातायात योजना का विकास।
- (2) शहर में गोदामों की शिफ्ट को सक्षम करने के लिए गोदामों/पूर्ति/एकत्रीकरण केंद्रों के विकास के लिए पेरी-शहरी स्थानों की पहचान।
- (3) टिकाऊ मोड आदि के माध्यम से माल का परिवहन।

#### 7. उत्तराखण्ड में निवेश हेतु फ्रेमवर्क:

##### i. औद्योगिक गलियारे

राज्य की रणनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आगामी दो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों से निकटता, अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य में लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचागत आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेंगे। राज्य सरकार राज्य के लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करेगी।

##### ii. वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, कंटेनर सुविधाएं और एयर कार्गो सुविधाएं बढ़ाना

- (क) कार्गो भण्डारण, सीमा शुल्क निकासी और कंटेनर उपलब्धता में चुनौतियों/कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार हरिद्वार और अन्य



उभरते औद्योगिक केंद्रों में नई अंतर्देशीय कंटेनर डिपो(आईसीडी)/शुष्क बन्दरगाह स्थापित करेगा।

- (ख) बनबसा, चंपावत में एक लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) के समन्वय से एक एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- (ग) काशीपुर और पंतनगर में मौजूदा आईसीडी और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर मौजूदा कार्गो सेटअप का उन्नयन करना।
- (घ) राज्य, पंतनगर हवाई अड्डे पर कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग के लिए एकीकृत सुविधाओं के साथ लॉजिस्टिक्स की सुविधा के लिए एक कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगा।
- (ङ) भारत के मेट्रो शहरों सहित गंतव्यों के लिए नई उड़ानें शुरू करके हवाई संपर्क बढ़ाया जायेगा।
- (च) कार्गो प्रवाह/बहिर्वाह को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार और रखरखाव, जिससे उद्योगों द्वारा किए गए लेन-देन की लागत को कम किया जा सके।
- (छ) सभी क्षेत्रों में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार से समन्वय।
- (ज) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल-वेदर चारधाम रोड परियोजना और भारतमाला सड़क परियोजना जैसी चल रही परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ भागों से संयोजकता बढ़ाना है।

iii. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग की स्थिति:

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 'बुनियादी ढांचे की स्थिति' की शर्तों को पूरा करने वाली वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इकाइयों को राज्य में 'उद्योग' का दर्जा दिया जाएगा।

iv. शुष्क बंदरगाहों को बढ़ावा देना:

उत्तराखण्ड सरकार उपयुक्त स्थानों (उच्च व्यावसायिक घनत्व) पर शुष्क बंदरगाहों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

v. भण्डारण सुविधाएं

एमएसएमई क्षेत्र (विशेषकर कृषि उत्पादक) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य का लक्ष्य प्रत्येक जिले में भण्डारण सुविधाएं विकसित करना है।

## vi. लॉजिस्टिक्स पार्क

राज्य सरकार सिडकुल के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास तथा लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी।

## vii. मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)

नौवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में, भारत के विभिन्न राज्यों में 7 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) प्रस्तावित किए गए थे, इनमें से एक पार्क लगभग 38 एकड़ के क्षेत्र में पंतनगर, उत्तराखण्ड में स्थापित किया गया है। इस सुविधा पर घरेलू संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय संचालन की सुविधा प्रदान करेगी। यह पार्क आईआईई पंतनगर और आसपास के क्षेत्रों जैसे रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और खटीमा में स्थित उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है, जहां पर प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उद्योग स्थापित हैं। यह पार्क रेल लिंक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में काम करेगा।

## viii. सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना

राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण में राज्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

## ix. कौशल विकास

उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के समन्वय से, राज्य क्षेत्र में बढ़ती मांग के लिए कुशल जनशक्ति को सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक्स विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

## 8. नीति का कार्यान्वयन

- i. यह नीति इसके अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मुद्दों, यदि कोई हो, अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष बाद प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आवश्यक संशोधनों को सम्मिलित कर तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
- ii. इस नीति में यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर इसे संशोधित या अधिक्रमित किया जा सकता है।
- iii. इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन होने पर, यदि राज्य सरकार पहले से ही किसी इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ प्रदान कर रही हो, तो उसे वापस



नहीं लिया जाएगा और इकाई निर्धारित अवधि तक लाभ की हकदार बनी रहेगी।

- iv. केंद्र सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी की किसी अन्य योजना के तहत समान परिसंपत्ति के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी।
- v. इस नीति के तहत प्रदत्त लाभ केवल तभी अनुमन्य होंगे, जब पूंजीगत व्यय के साथ-साथ परिचालन उद्देश्यों के लिए यूनिट के बिलिंग का पता उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हो।

#### 9. लॉजिस्टिक्स संस्थागत व्यवस्था

##### i. राज्य लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ (सेल)

एक अनुकूल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण के लिए, एक राज्य-स्तरीय लॉजिस्टिक्स सेल और स्टेट लॉजिस्टिक्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर सचिव, औद्योगिक विकास को सेक्टर के एकीकृत विकास के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

यह सेल लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन में परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को मापेगा और भविष्य की अवसंरचना व लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने, क्षमता की उपलब्धता और राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास की प्रवृत्तियों को सक्षम बनायेगा।

##### (क) राज्य लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ(सेल)

- |   |            |
|---|------------|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास,<br>उत्तराखण्ड शासन।  | अध्यक्ष    |
| 2. आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।   | सदस्य सचिव |
| 3. सचिव/अपर सचिव, नियोजन, वित्त, यातायात,<br>नागरिक उड्डयन, राजस्व, वन एवं पर्यावरण,<br>लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य      |
| 4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।  | सदस्य      |

##### (ख) राज्य लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति

- |  |            |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।                          | अध्यक्ष    |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास,<br>उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य सचिव |

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 3. | प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, वित्त, यातायात,<br>नागरिक उड्डयन, राजस्व, वन एवं पर्यावरण,<br>लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 4. | आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग/<br>निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।  | सदस्य |
| 5. | प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।   | सदस्य |
| 6. | क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य अधिकारी,<br>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।  | सदस्य |
| 7. | निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)।   | सदस्य |

यह भी प्रस्तावित है कि प्रमुख शहरों, जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी आदि के लिए नगर लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें नगर निगम, जिला प्राधिकरण आदि शामिल रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी माल ढुलाई क्षमता में सुधार और कार्गो आवाजाही को आसान बनाना तथा बाधाओं को दूर करना है।

#### 10. लॉजिस्टिक्स इकाइयों / पार्कों को प्रोत्साहन

नीति के माध्यम से सम्भाव्य और प्रत्याशित क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेप

उत्तराखण्ड राज्य की स्थलाकृति और लॉजिस्टिक आउटपुट के संदर्भ में आवश्यकताओं को देखते हुए इस नीति का उद्देश्य राज्य के भीतर एक हब-स्पोक मॉडल कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है, जिससे हब (मैदानों के रूप में वर्गीकृत जिलों) में बड़े लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और सुदूर के सम्बद्ध जिलों में मध्यम तथा छोटे स्पोक तैयार हो सकें। राज्य की भौगोलिक/स्थलाकृतिक आवश्यकताओं के आधार पर कंटेनरों और वाहनों में सामग्री के प्रवाह को समान रूप से आकार दिया गया है।

सम्भाव्य हब (स्तर 1): हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले।

- जहां हम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, वेयरहाउसिंग सुविधा, कोल्ड चेन सुविधा, बड़े ट्रक टर्मिनलों, ट्रांसपोर्ट/ट्रक मालिकों/फ्लीट ऑपरेटर्स/एग्रीगेटर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) के विकास की उम्मीद कर रहे हैं।
- लॉजिस्टिक्स पार्क मुख्य रूप से स्थित होगा
  - मौजूदा या प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक संपदा (आईआईई) पार्कों/एसआईडीसी/किसी भी प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर की परिधि से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी।



- किसी भी मौजूदा या प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर (रेलवे/राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग), या एयरबेस से अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) मुख्य रूप से निकटतम रेलवे स्टेशनों/एयरबेस के निकट स्थित होगा।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) के संबंध में अन्य नियम वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र संख्या 50/2020-कस्टम द्वारा जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे।

प्रशंसनीय मध्यम स्पोक्स (स्तर 2): स्तर 1 से 75 किलोमीटर से अधिक या उसके बराबर स्थान।

प्रशंसनीय छोटे स्पोक्स (स्तर 3): स्तर 2 से 50 किलोमीटर से अधिक या उसके बराबर स्थान।

नोट: ये स्थान राज्य के लिए रणनीतिक स्थान होंगे, अन्य स्थान ट्रंक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थान के अनुसार हो सकते हैं।

क्र.सं.	इकाइयां	मानदण्ड	प्रोत्साहन
(क)	सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधायें		
	(1) रु. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी(सब्सिडी) की अधिकतम सीमा रु. 8 करोड़ होगी।		
	(2) रु. 50 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी(सब्सिडी) रु.24 करोड़ तक सीमित होगी।		
	(3) रु. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी(सब्सिडी) रु. 32 करोड़ तक सीमित होगी।		
i.	गोदाम की (वेयरहाउसिंग) सुविधायें	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में न्यूनतम रु. 2.5 करोड़ निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की सुविधा और गैर-पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी-डी) के लिए रु. 5 करोड़ के निवेश के साथ न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
ii.	ट्रक टर्मिनल	रु. 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल में स्थापित ट्रक टर्मिनल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

iii.	परिवहन / ट्रक मालिक / प्लीट ऑपरेटर / एग्रीगेटर	कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन की खरीद (एक्स-शोरूम कीमत)।	बड़े पर 10 प्रतिशत और छोटे और मध्यम ट्रकों पर 15 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख
iv.	कोल्ड स्टोरेज	5,000 वर्ग फुट का न्यूनतम क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की जाने वाली सहायिकी(सब्सिडी) के अतिरिक्त दिया जाएगा।
v.	बुनियादी सुविधायें	बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि सुविधाएं, सीवेज और जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, फायर टैंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

क्र.सं.	इकाइयां	मानदण्ड	प्रोत्साहन
(ख)	विशेष लॉजिस्टिक्स इकाइयां		
	<p>(1) रु. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रु. 8 करोड़ होगी।</p> <p>(2) रु. 50 करोड़ से अधिक और रु. 150 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी अधिकतम सीमा रु. 24 करोड़ होगी।</p> <p>(3) रु. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रु. 32 करोड़ होगी।</p>		



i.	लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी/ड्राई पोर्ट/एयर कार्गो/इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क)	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में 05 एकड़ से अधिक और गैर-पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी डी) के लिए 10 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी/पीपीपी/जेवी मोड के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए गए।	(क)(i)-(क)(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।
ii.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कम से कम 18 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा।	(क)(i)-(क)(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।

(ग)	सभी श्रेणी के प्रोत्साहनों के अलावा
i.	कौशल विकास प्रोत्साहन (नए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के लिए— सामान्य या विशेष) सहायता के लिए प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 1 माह से अधिकतम 3 माह होगी।
ii.	रु. 25,000 का एकमुश्त समर्थन या प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण की वास्तविक लागत जो भी कम हो, संचालन की शुरुआत की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर अधिकतम 100 कर्मचारियों तक दिया जाएगा। कौशल विकास संस्थान को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी)/सरकार/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्(एआईसीटीई) के अधीन मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
iii.	कुशल श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के समन्वय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

## टिप्पणी:

1. ये प्रोत्साहन सभी नए और मौजूदा उद्योगों/लॉजिस्टिक इकाइयों, जिनका विस्तार हो रहा है, को अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार नियमित रूप से इस नीति की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसे और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
2. टर्मिनल ऑपरेटरों को टर्मिनल के भीतर एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखना होगा, जिसमें नियमित जांच की जाएगी और टर्मिनल के संचालक, जो भोजन और स्वच्छ आवास पर्यावरण के अनुरूप होने में विफल रहते हैं, ऐसे टर्मिनलों का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाएगा।

## 11. वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया

क्र. सं.	प्रोत्साहन जारी करने का चरण	चरण	चेकलिस्ट मॉडेलिटी (निवेशक द्वारा प्रस्तुत)
1.	प्रथम किश्त	भूमि क्रय के समय 10 प्रतिशत की पहली किश्त।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कंपनी निगमन प्रमाणपत्र।</li> <li>2. लैंड सेल डीड/लीज डीड।</li> <li>3. चार्टर्ड एकाउंटेंट से स्वीकृत डीपीआर।</li> <li>4. वित्त के साधन।</li> </ol> <p>सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।</p>
2.	दूसरी किश्त	लॉजिस्टिक नीति के अधीन कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की दूसरी किश्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत परियोजना पर उपयोग किया गया है।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिल वाउचर्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट तथा बैंक स्टेटमेंट: प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च।</li> <li>2. प्रोजेक्ट के लिए चुकाया गया माल और सेवा कर(जीएसटी) चालान।</li> <li>3. परियोजना स्थल के फोटो/वीडियो साक्ष्य।</li> <li>4. वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्णता प्रमाण पत्र (काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर से रजिस्ट्रीकृत वैध रजिस्ट्रीशन प्रमाण पत्र के साथ)।</li> </ol> <p>सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।</p>
3.	तीसरी किश्त	लॉजिस्टिक नीति के तहत कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की तीसरी किश्त जिला उद्योग केंद्र/उद्योग निदेशालय द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय वित्त के साधन और परियोजना लागत के 100 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है।</li> </ol>



		वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पुष्टि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समेकित सहमति और प्राधिकृत (सीसीए) जारी होने के बाद जारी की जाएगी।	<p>2. इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाओं/व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने का अपने जीएसटीआईएन नम्बर से जारी प्रथम बीजक की प्रति।</p> <p>3. जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) द्वारा जारी वाणिज्यिक संचालन प्रमाणपत्र।</p> <p>सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।</p>
4.	चतुर्थ किस्त	लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत कुल प्रोत्साहन राशि के 20 प्रतिशत की चौथी किस्त व्यावसायिक संचालन के 2 वर्ष बाद जारी की जाएगी।	<p>1. ऑडिट बुक/वार्षिक वित्तीय आख्या (रिपोर्ट) (वाणिज्यिक संचालन के 2 वर्ष पश्चात्)</p> <p>2. प्रोत्साहन की चौथी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले से स्वीकृत मदों के लिए प्रस्तावित/मूल्यांकित/वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर एक परियोजना लागत की पुनर्गणना की जाएगी और तदनुसार जारी की जाएगी।</p> <p>सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।</p>

टिप्पणी: "नीति के क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर संशोधित Environment protection Act, Wild life protection Act, Motor Vehicle Act एवं Labour Act से सम्बन्धित प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा"

इस नीति की अधिसूचना के बाद नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

आज्ञा से,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,  
सचिव।



In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 85/E-file-28344/VII-A-2/2023/02(4)/2022, dated January 31, 2023 for general information.

### Office Memorandum

*January 31, 2023*

No. 85/E-file-28344/VII-A-2/2023/02(4)/2022--To encourage the integrated development of the logistics sector in accordance to the vision of Government of India in the State, to extend its support to new and existing industries operating in the field of logistics sector, primarily to reduce logistics costs, with the aim of strengthening the existing logistics infrastructure, creating employment opportunities, increasing the ranking of the state in the Logistics Index and increasing investment in this sector by providing financial and non-financial assistance, the Governor is pleased to allow to make an "The Uttarakhand Logistics Policy, 2023".

### **"The Uttarakhand Logistics Policy, 2023".**

#### **1. Preamble**

Uttarakhand, located in the foothills of the Himalayan mountain range, is rich in natural resources. The state shares inter-state borders with China (Tibet) in the north, Nepal in the east, Himachal Pradesh in the west and north-west and Uttar Pradesh in the south. Due to its proximity to the National Capital Region, the state has easy access to important markets as well as the availability of raw materials. The state has immense potential for export in organic agricultural products, agro-based and processed food, aromatic and medicinal plant-based products, pharmaceuticals, nutraceuticals and service sectors such as tourism and wellness.

After the formation of Uttarakhand as a new state in the year 2000, as a result of the Special Industrial package sanctioned by the Government of India for the state of Uttarakhand in the year 2003, there has been rapid industrialization in Uttarakhand. By forming the State Infrastructure and Industrial Development Corporation Uttarakhand Ltd., Integrated Industrial Estates with world-class industrial infrastructure facilities were established in the state, as a result of which the reputed industrial houses of the world and the country established their manufacturing units here. The State has also notified a policy for Private Industrial Estates/ Areas with the participation of the private sector in the state. Industry-friendly policies and conducive environment for industrial development have helped Uttarakhand emerge as an attractive investment destination.

The State's Gross Domestic Product (GSDP) has increased from Rs. 1, 77, 163 to Rs. 2, 53, 666 in the year 2015-16 at the rate of 9.48 per cent in the last five years. In the year 2020-21 during COVID, the state's Gross Domestic Product (GDP) has declined by 4.2%, which is likely to increase from Rs. 2,43,012.3 lakh to Rs. 2,78,006 lakh in future. Cumulative Foreign Direct Investment (FDI) in Uttarakhand has increased 10 times from Rs. 80.7 crores to Rs. 918 crores in the last two years (December 2019 – December 2021). During the year 2014-15 to the



year 2020-21, India's inclusive negative growth rate in exports from Uttarakhand was estimated at 0.91 percent, relative to which the state has registered a compound annual growth rate of 6.38 percent (US\$ 2.14 billion).

Uttarakhand is one of the top-ranking states of India in the ranking of Ease of Doing Business organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Business Reform Action Plan 2019-20 in collaboration with the World Bank.

In the Export Preparedness Index 2020 report released by NITI Aayog, Government of India in August 2020, Uttarakhand has been identified as the top performing state in the Himalayan state's category. This has been made possible by the presence of basic export facilities and infrastructure, a conducive trade and export environment as well as good export performance by the state. In the report of the year 2021, the state has maintained its first position among the Himalayan states.

Uttarakhand has been ranked 13<sup>th</sup> in the Logistics Ease Across Different States (LEADS) Index released by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India in March 2021. The state being a landlocked state incurs an inherent adverse cost to the state's exporters as compared to other states, because they have to bear high logistics costs in bringing the raw materials to their premises as well as shipping the finished products. Despite these challenges, Uttarakhand has exported goods and services worth about Rs. 15,915.54 crore during the year 2020-21.

It is the belief of the State Government that the development of infrastructure facilities in the logistics sector is very important to achieve the goal of sustainable and continuous industrial development in the State. The development of this sector will not only encourage manufacturing and employment generation in the state but will also increase the state's gross domestic product. In the light of the above facts, Uttarakhand Government has decided to promulgate the Uttarakhand Logistics Policy, 2023 with the intention of taking maximum benefits for economic and industrial development in view of the strategic geographical location of the state. This policy is being promulgated with the intention of extending its support to the new and existing industries working in the field of logistics in the State, in line with the vision of the Central Government for integrated development of the logistics sector and the objective of this policy is to reduce the logistics cost. To strengthen the existing logistics infrastructure, generate employment opportunities and increase the ranking of the state in logistics index and attract investment in this sector by providing financial and non-financial support.

2.

#### **Definitions:-**

In order to allow the financial incentives provided in this policy, the logistics park and other logistics units have been defined as follows:-

- (a) **"Logistics"** means to the overall process of logistics management that collects and transports resources to their final destination.
- (b) **"Logistics services"** means to cargo aggregation/ separation, distribution, intermodal transfer of materials and containers, open and closed storage, conditions suitable for storage in the cargo transit period, material handling equipment and trade and commercial facilities and common facilities.
- (c) **"Eco-logistics or green logistics"** means techniques that aim at minimizing the ecological impact of logistics activities, including eco-friendly transportation, reducing carbon emissions, solid-liquid waste management, scientific disposal



techniques, use of bio-degradable items, adopting recycling techniques, using renewable energy, etc.

- (d) **"Supporting infrastructure"** means development of internal roads, communication facilities, open and green spaces, water pipelines, sewage/ drainage and disposal facilities, power lines, feeders, solar panels and other facilities as per the requirements of the Logistics Park.
- (e) **"Inland Container Depot"** means an off-sea port facility with a fixed installation or otherwise, providing services for operation of equipment, machinery, etc., and/ or Licensing facility from Customs control including facility for storage of Laden Import/ Export containers with custom bonded or non-bonded cargo. These facilities include road connectivity, rail connectivity, customs/ non-custom bonded warehousing, truck terminals, etc. and other common utilities required for efficient operation. Inland container depot means with minimum investment of Rs. 50 crore and minimum area of 18 acres.
- (f) **"Air Cargo Complex"** means the facilities developed to enhance the air cargo movement capacity of the State. These facilities can be located within airport/ off-airport locations and provide facilities such as handling, storage and clearance of cargo, among other facilities.
- (g) **"Warehouse"** means an open/ closed area developed to provide storage facilities for any cargo. To provide facilities in bulk/ break bulk form for handling and storage of warehouse cargo. Warehouse facility with minimum investment of Rs. 2.5 crore and area 5,000 square feet in hilly area (Category A, B, B+ and C) and minimum investment of Rs. 5 crores with minimum area of 10,000 square feet for non-hill area (Category - D).
- (h) **"Cold chain facility"** means a facility for storage and minimal processing of perishable/ temperature sensitive cargo like agriculture, horticulture, dairy, fish and marine, poultry and meat products, pharma, etc. which is linked from source to consumer. Cold chain facility with an investment of Rs. 5 crore and minimum area of 5,000 sq. ft.

**The major components of cold chain facilities may include:**

- (i) Controlled Atmosphere/Modified Atmosphere Chamber, Variable Humidity Chamber, Ambient Storage, Individual Quick Freezing, Blast Freezing etc.
- (ii) Weighing, sorting, grading, cleaning, waxing, packing, pre-cooling, fog treatment, irradiation etc. facilities at Minimal Processing Center.
- (iii) A dedicated cold chain facility with end-to-end mobile pre-cooling vans and reefer trucks.
- (i) **"Truck terminals"** mean such facilities which are developed to reduce traffic congestion at strategic locations such as district logistics nodes, industrial areas, national/ state highways, expressway intersections etc. Truck terminals provide facilities such as repair and maintenance of trucks, stores for spare parts, ATMs, fuel stations, parking spaces, transportation offices, sanitation facilities, weighbridges etc. These facilities may include facilities for loading/ unloading (cross-docking) cargo as well as accommodation for drivers and their assistants, among other facilities. Automated vehicle fitness checks can also be provided at truck terminals. Truck terminal with an investment of Rs 5 crore and minimum area of 45,000 sq. ft.
- (j) **"Logistics parks"** means facilities which provide services such as cargo aggregation/ segregation, distribution, inter-modal transfer of cargo and containers,



open and/ or closed storage, temperature controlled and/ or ambient storage, custom bonded warehouse, material handling equipment, parking, value added services and other related facilities as per requirement for efficient movement and distribution of semi-finished or finished products. Logistics parks shall be equipped with supporting infrastructure including internal roads, communication facilities, open and green spaces, water pipelines, sewage and drainage lines, power lines, feeder and other facilities as per the requirements of the park.

- (k) **“Transports/ Truck Owners/ Fleet Operators/ Aggregators”** means purchasing a minimum number of 3 Trucks/ Small Trucks / Mini Pickup trucks/ Refer vans (Ex-Showroom Price as applicable). The categorization of trucks are done on the basis of following criteria:-

- (i) Big Truck: (32-40 Feet, 14-Wheeler Truck (21 Ton To 31 Ton Capacity))
- (ii) Medium Trucks: (24-32 Feet, 12-Wheeler Truck (16 Ton To 25 Ton Capacity))
- (iii) Small/Mini Pick-ups Trucks: (20-32 Feet, 10-Wheeler Truck (10 Ton To 15 Ton Capacity))

- (l) **“Expansion”** means an increase in the value of the capital investment in immovable fixed assets like Plant and Machinery and factory Buildings (excluding working capital and Cost of Land); of capital investment in existing unit/ project by at least 25 percent, with enhancement of at least 25 percent of existing capacity.

- (m) **“Project Cost”** means investment in Super built-up area\* of a logistics unit, Plant and machinery and factory building (In case of new unit/project) excluding working capital and Cost of Land.

*\*Super Built-up Area is defined as the total sum of the built-up area and the space that has been occupied by the common areas such as staircase, lobby, elevator, clubhouse, shafts etc. Super built-up area is also referred to as the “saleable area” on which the developers usually base the final charge.*

- (n) **“Hub and Spoke network”** means a centralized, integrated logistics system designed to keep costs low. Hubs and spoke distribution centres receive products from several different origin producers/ suppliers, integrating them and sending them directly to the destinations.

### 3. Eligibility

- (i) Entity/ Institution registered as Sole Proprietorship, Partnership Firm, Co-operative Society, Company, Limited Liability Partnership (LLP), Trust, Non-Governmental Organization (NGO) and any other legal entity can avail the benefit of financial incentives under this policy.
- (ii) The benefits of the facilities provided in the policy will also be admissible to the Public Sector undertakings (PSUs) of the Central or State Government or the projects of Public- Private Partnership (PPP) mode.
- (iii) Units in the logistics sector that avail financial incentives under any other policy or from any other department of the Central/ State Government will not be eligible to get the incentives/ benefits mentioned in this policy as consolidated incentives have been provisioned here.
- (iv) According to the definition given for the substantial expansion of the existing industrial unit in the State's Micro, Small and Medium Enterprises Operational Order 2015 (as amended from time to time), it is necessary to make additional fixed capital investment of minimum 25 percent or more in the existing capital



investment of the existing unit.

- (v) The entity registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Identification Number only will be eligible to claim the incentive assistance provided in the Policy.
- (vi) Only the amount mentioned in the invoice issued on Uttarakhand based Goods and Services Tax Identification Number will be taken into account for the purpose of incentives.

#### 4. Vision

- (i) Facilitation and development of an integrated logistics ecosystem in Uttarakhand will help enhance competitiveness, operational efficiency and sustainability through innovation, skilled manpower, quality and disruptive technology. This will reduce the cost of logistics as well as boost trade and private investment in Uttarakhand.
- (ii) The policy aims to address the cross-functional needs of the entire value chain of the ecosystem in Uttarakhand. It is a step towards enhancing and promoting the business needs of Logistics Enablers, Investors and Service Providers. This policy has been prepared to create a hub-spoke logistics ecosystem within the State.

#### 5. Objectives of Policy

- (i) Creation of a simplified, proactive and responsive institutional mechanism for rapid growth of the logistics sector.
- (ii) Strengthening of new and existing logistics infrastructure like godowns, Inland Container Depot (ICD), cold storage, rail-road connectivity to industrial estates/clusters etc.
- (iii) To develop hub-spoke logistics model in the State to strengthen economic linkages between hilly and plain areas and create benefits across the entire business value chain for logistics.
- (iv) To promote green and innovative practices to develop competitive logistics infrastructure in the State.
- (v) To encourage private investment for setting up logistics facilities in the state with forward and backward linkages.
- (vi) Upgradation and improvement of existing warehousing and logistics infrastructure facilities to promote economic activities and large-scale employment.
- (vii) To provide handholding support to existing and new logistics operators.
- (viii) Coordination with all national and global agencies involved in promoting logistics.
- (ix) To develop competitive logistics infrastructure facilities in the state by promoting green and innovative logistics.

#### 6. Strategies

- (i) **Creation of a simplified, proactive and responsive institutional mechanism for rapid growth of the logistics sector.**
  - (a) Mapping of logistics facilities across the state to identify areas of intervention/improvement and development.
  - (b) Identification of potential and operational constraints for the proposed development of existing logistics facilities, services, road and rail networks at the state and national levels.



(c) Assessing the future requirements of logistics infrastructure such as rail networks, airports and logistics facilities.

(d) To consider the focus areas of MSME Policy, 2015, Mega Industrial and Investment Policy, 2021 and other similar policies promulgated by the Government of Uttarakhand.

(ii) **Strengthening of new and existing logistics infrastructure like godowns, Inland Container Depot (ICD), cold storage, rail-road connectivity to industrial estates/ clusters etc.**

The objectives of this Policy is to improve utilization of existing logistics facilities, which are under the control of private developer or various State Government Departments/ agencies. The existing facilities will be evaluated on the basis of various performance parameters to improve their utilization through relevant stakeholder consultations.

(iii) **To promote green and innovative practices to develop competitive logistics infrastructure in the State.**

(a) The aim of the Uttarakhand Government is to build an eco-friendly and sustainable logistics and transport system in the state. Green logistics are technologies that aim to reduce the ecological impact of logistics activities, including eco-friendly transportation, reducing carbon emissions, solid-liquid waste management, scientific disposal techniques, use of bio-degradable goods, recycling techniques. Adoption, use of renewable energy etc. Thus, the policy will promote the use of electric and hybrid vehicles in multimodal transport and logistics parks along with promoting green logistics initiatives.

(b) The state will implement smart systems for efficient movement of cargo through checkpoints. "Green Channels" will be identified for vehicles carrying export-import/Defence Cargo.

(iv) **Promoting private investment in setting up of logistics facilities with forward and backward linkages in the state.**

(a) The Government of Uttarakhand will encourage Public Private Partnership in the creation of modern logistics facilities in the state.

(b) **Development of storage and handling facilities:** The policy focuses on development of warehousing and handling facilities at strategic nodes for improvement of logistics efficiencies in focus areas like pharmaceuticals, e-commerce, agricultural products etc.

(c) **Development of Air Freight Stations and Air Cargo Complex at Strategic Locations:** Air cargo capacity, existing capacity constraints, air connectivity etc. will be assessed in this Policy. Accordingly, while mapping the facilities for promotion of air cargo, priority will be given to the development of air cargo terminals and air freight stations.

(d) **Supported development of e-commerce:** The Policy encourages development of e-commerce hubs in high-speed areas, near demand points and around the periphery of cities. It will cater to the needs of the e-commerce sector as well as congest the traffic in the cities.

(e) **Development of Truck Terminals, Driver Rest Areas and Parking Spaces:** The policy will promote repair and maintenance of truck terminals,



driver rest areas and development of parking spaces at strategic locations (National/ State Highways, Expressway intersections etc.) around the periphery of industrial parks and high cargo density. This will decongest the crowd and provide proper waiting area for trucks during restricted hours in the city.

v. **To provide fiscal and non- fiscal incentives to the logistics companies by the Uttarakhand Government to promote sector specific.**

The Government of Uttarakhand will provide financial and non-financial incentives to logistics companies to promote the sector. This Policy promotes and encourages the use of new technology for improving the capacity of the sector in Uttarakhand. Following are some examples of technology that can be adopted for this purpose:

- (a) Robotics and automation in material handling, cargo transportation and easing cargo traffic at logistics facilities.
- (b) Blockchain technology-based systems for verification of transactions and exchange of documentation and information in a secure manner.
- (c) Digital twin technology to measure the impact of new experiments in simulation construction and layout and new machinery etc. in a risk-free manner. This technique identifies recurring trends and potential vulnerabilities in the operating environment, providing input for future improvements.
- (d) The use of artificial and augmented intelligence tools for advanced demand planning, route planning, operation planning etc. has resulted in reduction of time period, human errors and cost. Artificial intelligence-based technologies also provide the best route options for lower carbon emissions, thereby supporting environmental sustainability initiatives.
- (e) The objective of the Policy is to promote innovation in logistics by encouraging technology patent registration by technology providers, start-ups and other business entities and/ or by implementing specialized technology solutions during the policy period. In addition, awards/ annual awards for best technology and innovative solutions in the logistics sector will also be instituted.

**Note:** The mega projects of special importance (new technology based) will be considered for sanctioning customized packages on a case-to-case basis. According to the provisions of the Uttarakhand Enterprise Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012, the State Level Empowered Committee constituted under the chairmanship of Chief Secretary will recommend customized package of incentives.

vi. **Providing support to existing and new logistics operators in the state (Ease of Doing Logistics)**

As a part of the ongoing business reforms and to obtain the statutory approvals from the concerned departments, to streamline the existing logistics processes, aim is to simplify standard operating procedures through process re-engineering and digitizing the existing processes involved in grant of approvals. An online Single Window System is already in place and will be strengthened for online application submission, payment, tracking, approval etc., which will remove physical touch points in all levels, requiring physical verification. In order to ensure that the application is approved within the time limit, as per the Uttarakhand Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 will be followed.



vii. **Coordinating with all national and global agencies involved in promoting logistics.**

The state government will assist in identifying potential export markets. It will tie up with export promotion desks by tying up with business centres in embassy offices abroad.

To enhance logistic competitiveness in the state, the government will take advantage of schemes like Trade Infrastructure for Exports Scheme (TIES), Micro and Small Enterprises Cluster Development Program (MSE-CDP) etc.

The State Government will take steps to strengthen the existing logistics and export ecosystem and establish camp offices of the relevant Export Councils in the State and will also collaborate with other export promotion organizations like Federation of Indian Export Organization, Indian Institute of Foreign Trade, Engineering Export Promotion Council, Service Export Promotion Council, Export Credit Guarantee Corporation, Tea Board etc.

viii. **Keeping the above objectives in view, a comprehensive logistic plan has to be developed and implemented for the state of Uttarakhand.**

The Government of Uttarakhand will develop and implement a comprehensive logistics plan with a focus on four key areas of logistics:

(a) **Driver Empowerment and Employment:** Identification of dedicated parking and resting places for trucks and their drivers along highways and major roads.

(1) Schemes for training and skill up-gradation.

(2) Development of primary facilities/ centres in the state highways providing infrastructure.

(3) Administering state specific schemes for the health and welfare of drivers.

(4) Organized driver training programs by State Skill Mission.

(b) **Warehousing:** Fixation of standards in respect of easy availability of land and convenient environment for conversion of land use, relaxation in Floor Area Ratio (FAR) for warehousing, height of godowns etc.

(1) Arrangement for obtaining permission and approval for establishment and operation of godowns under Single Window Facilitation and Clearance Act-2012.

(2) Preparation of e-directory of godowns in the state.

(c) **Smart Enforcement:** Developing eco-system for minimum inspection and stoppage of trucks on the road. Removal of obstacles by identifying truck movement checkpoints and effective implementation of Roads Act, 2007 and Indian Motor Vehicles Act for carriage of goods.

(1) Simplification of existing procedures for road enforcement.

(2) Initiatives to address protruding cargo.

(3) To prepare a roadmap for adoption of an alternative/ innovative method of enforcement.



- (4) Provision of WiFi/ CCTV/ WIM for remote enforcement.
- (5) Integration of GSTN/ FASTag/ Vahan/ Sarathi database and use in smart enforcement.
- (d) **City Logistics:** Logistics park/ transport infrastructure with truck parking/ warehousing in peri-urban areas near cities and traffic arrangements for last-mile delivery.
  - (1) Development of transport infrastructure and traffic planning for last mile delivery within city limits.
  - (2) Identification of peri-urban locations for development of godowns/fulfilment/aggregation centres to enable shifting of warehouses in the city.
  - (3) Transport of goods through sustainable mode etc.

7.

### **Framework for Investment in Uttarakhand**

#### **(i) Industrial Corridors**

The state's strategic location and proximity to the National Capital Region (NCR) and the upcoming two National Industrial Corridors, Amritsar Kolkata Industrial Corridor and Delhi Mumbai Industrial Corridor will help meet the infrastructural requirement to facilitate logistics activities in the state. The State Government will take special measures to enhance the logistics and infrastructure of the State.

#### **(ii) Increasing Warehousing, Storage, Container Facilities and Air Cargo Facilities**

- (a) To overcome the challenges/ difficulties in cargo storage, customs clearance and container availability, the State Government will set up new Inland Container Depot (ICDs)/ Dry Ports at Haridwar and other emerging industrial hubs.
- (b) A Land Custom Station at Banbasa, Champawat will be set up as an integrated check post in coordination with the Land Port Authority of India.
- (c) Upgradation of existing ICDs at Kashipur and Pantnagar and existing cargo setup at Jolly Grant airports.
- (d) The state will set up a cargo terminal at Pantnagar airport to facilitate logistics with integrated facilities for cold chain and warehousing.
- (e) Air connectivity will be increased by introducing new flights to destinations including metro cities of India.
- (f) Improvement and maintenance of existing road infrastructure in industrial areas to increase cargo inflow/ outflow thereby reducing the cost of transactions undertaken by the industries.
- (g) Coordination with Government of India to increase rail connectivity in all areas.
- (h) Ongoing projects like Rishikesh-Karnprayag Rail Project, All-Weather Char Dham Road Project and Bharatmala Road Project are aimed at increasing connectivity to remote parts of the state.

#### **(iii) Industry Status to Logistics Sector**

Warehousing and logistics units that meet the conditions of 'infrastructure status' as prescribed by the Government of India will be given 'industry' status in the state.



(iv) **Promote Dry Port**

The Uttarakhand government will focus on strengthening dry ports and inland container depots at suitable locations (high commercial density).

(v) **Storage Facilities**

The state aims to develop warehousing facilities in each district to meet the needs of the MSME sector (especially agricultural producers).

(vi) **Logistics Park**

The State Government will provide assistance in the development of necessary infrastructure and setting up logistics parks through SIIDCUL.

(vii) **Multimodal Logistics Park**

As part of the National Perspective Plan prepared under the Sagarmala Program of the Ministry of Shipping, 7 Multi-Modal Logistics Parks were proposed in different states of India, out of which one park has been set up in Pantnagar, Uttarakhand in an area of about 38 acres. Domestic operations have already been started at this facility and the state government will facilitate international operations. The park is supporting industries located in IIE Pantnagar and adjoining areas like Rudrapur, Kashipur, Kichha and Khatima where industries of major industrial establishments are established. The park will serve as a rail linked multimodal logistics park.

(viii) **Encouraging Public-Private Partnerships**

The state will encourage public-private partnerships in the creation of modern logistics facilities in the state.

(ix) **Skill Development**

In coordination with the Uttarakhand Skill Development Mission, the subject of logistics will be included in the curriculum to enable skilled manpower to meet the increasing demand in the state sector.

**8. Policy Implementation**

- (i) This Policy will be effective from the date of its notification and will remain in force for 5 years. This Policy shall be reviewed after 2 years from the date of notification on progress made and on implementation related issues, if any. Necessary amendments will be incorporated and notified accordingly.
- (ii) This Policy may be amended or superseded from time to time, if necessary.
- (iii) On amendment of any of the provisions of this Policy, if the State Government is already providing the benefit of financial incentive to any unit, the same will not be withdrawn and the unit will continue to be entitled to the benefit for the prescribed period.
- (iv) A unit that has availed any incentive for the same assets under any other scheme of the Central Government/ State Government, or any agency of the state government shall not be eligible for incentive under this scheme.
- (v) Benefits under this Policy will only be applicable in case the unit's billing address is located in Uttarakhand for capital expenditure as well as for operational purposes.



## 9. Logistics Institutional Cell

### (i) State logistics Cell

In order to create a conducive logistics ecosystem, a State-level Logistics Cell and State Logistics Coordination Committee will be constituted and Secretary, Department of Industry, will be nominated as the nodal officer for the integrated development of the sector.

This cell shall measure the performance metrics across the logistics value chain and enable data-driven decision-making for future infrastructure and logistics projects, the availability of capacity and growth trends for logistics infrastructure and facilities in the State.

#### State logistics Cell

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Principal Secretary/Secretary, Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand.   | Chairperson      |
| 2. Director General and Commissioner Industries, Uttarakhand.  | Member Secretary |
| 3. Secretary/Additional Secretary, Planning, Finance, Transport, Civil Aviation, Urban Development, Revenue, Forest and Environment, Public Works Department (PWD), Government of Uttarakhand. | Member           |
| 4. Managing Director, SIIDCUL  | Member           |

#### State Logistics Coordination Committee

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Chief Secretary, Uttarakhand  | Chairperson      |
| 2. Principal Secretary/ Secretary, Department of Industry, Government of Uttarakhand.  | Member Secretary |
| 3. Principal Secretary/Secretary, Planning, Finance, Transport, Civil Aviation, Urban Development, Revenue, Forest and Environment, Public Works Department (PWD), Government of Uttarakhand | Member           |
| 4. Director General and Commissioner Industries, Uttarakhand.  | Member           |
| 5. Managing Director, SIIDCUL  | Member           |
| 6. Regional Officer/Chief Officer, National Highways Authority of India (NHAI)   | Member           |
| 7. Director, Airports Authority of India (AAI)   | Member           |

It is also proposed that City Logistics Coordination Committee will be formed for major cities like Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar, Haldwani, in which Municipal Corporation, District Authority etc. will be included. Its main objective is to improve urban freight carrying capacity and ease cargo movement and remove bottlenecks.



**10. Incentives to Logistics Units/Parks****Strategic interventions in potential and promising areas through policy**

Keeping in view the requirements in terms of topography and logistic output of the state of Uttarakhand, the objectives of this Policy is to build a hub-spoke model concept within the state, leading to development of large logistics connectivity and infrastructure in hubs (districts classified as plains) and to prepare medium and small spokes in the remotely connected districts. The material flow in containers and vehicles will be equally sized, depending on the geographical/ topographical requirements of the state. Plausible and Expected outcome of this Policy and the intent behind the Policy:

**Plausible Hubs (Level 1):** Districts of Haridwar, Dehradun, Udham Singh Nagar and Nainital.

- Where we are Expecting Development of Air Cargo Complexes, Warehousing facility, Cold Chain Facility, Big Truck Terminals, Transports/ Truck Owners / Fleet Operators/ Aggregators, Logistics Park, Inland Container Depot (ICD).
- Logistics Park shall be predominantly located at a
  - Maximum distance of 10 Kms from periphery of existing or proposed Integrated Industrial Estate (IIE) Parks / SIDCs / any proposed industrial cluster.
  - Maximum distance of 3 Kms from any existing or proposed trunk infrastructure (Railways/ State Highway/ National Highway), or Airbase.
- Inland Container Depots (ICD)/Container Freight Station (CFS) shall be predominantly located in the proximity to the nearest railway stations/ Airbase.
- Other regulations regarding Inland Container Depots (ICD)/ Container Freight Station (CFS) shall be as per Central Government notification issued by Ministry of Finance vide circular no.50/2020-Custom.

**Plausible Medium Spokes (Level 2):** Locations greater than or equal to 75 Kms from Level 1

**Plausible Small Spokes (Level 3):** Locations greater than or equal to 50 Kms from Level 2

Note: These locations shall be strategic locations for the state, other locations may come as per availability of trunk infrastructure, land availability, and suitable location as per requirement.

S.No.	Units	Criteria	Incentive
<b>(A.) General Logistics Facilities</b>			
(1) For project cost of up to Rs. 50 crores, subsidy will be capped at Rs. 8 cr			
(2) For project cost of more than Rs. 50 cr and up to Rs.150 cr, subsidy will be capped at Rs. 24 cr			
(3) For project cost of more than Rs. 150 cr, subsidy will be capped at Rs. 32 cr			
i.	Warehousing facility	Warehouse facility with minimum investment of Rs. 2.5 crore and area 5,000 square feet in hilly area (Category A, B, B+ and C) and minimum investment of Rs. 5 crores with minimum area of 10,000 square feet for non-hill area (Category - D).	20 percent of the Project cost
ii.	Truck Terminal	Truck terminal with an investment of Rs. 5 crore and minimum area of 45, 000 sq. ft.	20 percent of the Project cost



iii.	Transports/ Truck Owners / Fleet Operators/ Aggregators	Purchasing minimum number of 3 Trucks/ Small Trucks / Mini Pickup trucks/ Refer vans (Ex-Showroom Price)	10 percent on Big and 15 percent on small and medium trucks, upto Rs. 10 Lakhs
iv.	Cold Storage	Minimum area of 5,000 sq. ft.	15 percent of the Project cost additional to the subsidy provided for cold storage by the Central Government
v.	Infrastructure Facilities	Internal Transportation system, Power line, Communication facilities, Water distribution and water augmentation facilities, Sewage and drainage lines, Effluent treatment and disposal facilities, Fire tender arrangements, Parking, Weigh bridge, Medical Centre	20 percent of project cost

S.No.	Units	Criteria	Incentive
<b>B. Special Logistic Units</b>			
(1) For project cost of up to Rs. 50 crores, subsidy will be capped at Rs. 8 cr			
(2) For project cost of more than Rs. 50 cr and up to Rs.150 cr, subsidy will be capped at Rs. 24 cr			
(3) For project cost of more than Rs. 150 cr, subsidy will be capped at Rs. 32 cr			
i.	Logistics Park (MMLP/Dry Port/Air Cargo/ Integrated Logistics Park)	Logistics Parks developed on basis of Private/PPP/ JV mode on land above 05 acres in hilly area (Category A, B, B+ and C) and more than 10 acres for non-hill area (Category D).	Incentive as per Facilities constructed, as listed in A(i)-A(v)
ii.	Inland Container Depot (ICD)	ICD shall be made in minimum area of 18 acres.	Incentive as per Facilities constructed, as listed in A(i)-A(v)

**C. Over and above, all category of incentives –**

i.	Skill development Incentive (For new logistics provider- general or special) With training period of 1 Month(minimum) to 3 Months(maximum)
ii.	One time support of Rs. 25,000/- or actual cost of training per person whichever is lower, up-to maximum of 100 Employees to be claimed within a period of 2 years from the starting date of operations. Skill Development Institution needs to be accredited under National Skill Development Corporation (NSDC)/University Grants Commission (UGC)/ Government/ All India Council for Technical Education (AICTE).
iii.	In order to enhance the availability of skilled labour, Vocational courses shall be initiated in coordination with the institutes of national importance.



**Note:**

1. These incentives will apply to all new and existing industries / logistics units and those units that undergo expansion, Government of Uttarakhand will regularly review the progress of this Policy and take necessary steps to make it more effective and result-oriented.
2. Terminal operators shall have to maintain a hygienic environment within terminal, wherein regular check-up shall be done and operators of terminal, who fails to align with food and hygienic lodging environment conformation, registration of such terminals shall be discontinued.

**11. Process of obtaining financial incentives**

S. No.	Phase of Incentive Release	Stages	Checklist Modality (Submission by Investor)
1.	1st Instalment:	The 1st instalment of 10 percent at the time of Land Purchase.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Company Incorporation Certificate</b></li> <li>2. <b>Land Sale Deed/ Lease Deed</b></li> <li>3. <b>Approved DPR from Chartered Accountant</b></li> <li>4. <b>Means of Finance</b></li> </ol> <p><i>All documents can be uploaded through Online mode and verification on designated website, fund shall be disbursed</i></p>
2.	2nd Instalment:	The 2nd instalment of 35 percent of the total Incentive under the Logistics Policy will be released after ensuring that 90 percent of the project cost has been utilized on the project.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bill Vouchers, Proof of Payments, Bank Statement:</b>Expenditure incurred on the project</li> <li>2. <b>GST challan</b> paid for project</li> <li>3. <b>Photo/Video</b> evidence of Project site</li> <li>4. <b>Completion Certificate</b> by duly signed by Architect (registered with Council of Architecture having a valid registration certificate)</li> </ol> <p><i>All documents can be uploaded through Online mode and verification on designated website, fund shall be disbursed</i></p>
3.	3rd Instalment:	The 3rd instalment of 35 percent of the total Incentive under the Logistic Policy will be released only after confirming the commencement of commercial production through physical verification by the District Industries Centre / Directorate of Industries and issue of Consolidated consent & authorization (CCA) from the Pollution Control Board	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Chartered Accountant Certificate</b>— Actual expenditure incurred on the project showing the means of finances and 100 percent utilization of Project Cost</li> <li>2. <b>Copy of the first invoice</b> issued by the entity from its GSTIN number for the services provided/commencement of business activity.</li> <li>3. <b>Commercial Operation Certificate</b> issued by DIC</li> </ol> <p><i>All documents can be uploaded through Online mode and verification on designated website, fund shall be disbursed</i></p>



S. No.	Phase of Incentive Release	Stages	Checklist Modality (Submission by Investor)
4.	4th Instalment:	The 4th instalment of 20 percent of the total Incentive under the Logistic Policy will be released only after 2 years of commercial operation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit book/ Annual Financial Reports (after 2 years of Commercial Operation)</li> <li>2. Before releasing of 4th &amp; final instalment of Incentive a project cost will be re-calculated based on the proposed/ appraised / actual cost, whichever is less, for the already approved items and released accordingly</li> </ol> <p><i>All documents can be uploaded through Online mode, and verification on designated website, fund shall be disbursed</i></p>

Note: For the implementation of the policy, compliance with the provisions related to Environment Protection Act, Wild Life Act, Motor Vehicle Act and Labor Act, as amended from time to time, will also be ensured.

After the notification of this Policy, detailed guidelines will be issued separately for the implementation of the Policy.

By Order,

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,  
Secretary.





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2023 ई0 (फाल्गुन 06, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 19, 2023

No. 27/XIV-a-37/Admin.A/2016--Ms. Soniya, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 01.12.2022 to 20.12.2022.

NOTIFICATION

January 19, 2023

No. 28/XIV-a-33/Admin.A/2020--Shri Prateek Mathela, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 35 days w.e.f. 18.11.2022 to 22.12.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).



NOTIFICATION*January 19, 2023*

No. 29/XIV/55/Admin.A/2003--Shri Nitin Sharma, Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 26.12.2022 to 13.01.2023. with permission to prefix 25.12.2022 as Sunday holiday and suffix 14.01.2023, 15.01.2023 as second Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION*January 19, 2023*

No. 30/XIV-22/Admin.A/2008--Shri Vivek Srivastava, Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 12.12.2022 to 17.12.2022 with permission to prefix 10.12.2022 & 11.12.2022 as second Saturday and Sunday holiday respectively and suffix 18.12.2022 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

*Sd/-*

*Registrar General.*

NOTIFICATION*January 19, 2023*

No. 31/XIV-a-52/Admin.A/2020--Shri Shiv Singh, Judicial Magistrate-II, Haridwar is hereby sanctioned Paternity leave for 15 days w.e.f. 01.12.2022 to 15.12.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

*Sd/-*

*Registrar (Inspection).*

NOTIFICATION*January 19, 2023*

No. 32/XIV-31/Admin.A/2008--Shri Madan Ram, Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 12.12.2022 to 17.12.2022. with permission to prefix 10.12.2022 & 11.12.2022 as second Saturday and Sunday holiday respectively and suffix 18.12.2022 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

*Sd/-*

*Registrar General.*

NOTIFICATION

January 20, 2023

No. 33/XIVa-28/Admin.A/2021--Ms. Udisha Singh, Judicial Magistrate-II, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 31 days w.e.f. 14.11.2022 to 14.12.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2023 ई० (फाल्गुन 06, 1944 शक सम्वत्)

### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

### कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

#### अधिसूचना

#### (सूचना)

17 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक 136/त्रि०पं०/उप-निर्वाचन/स०ग्रा०पं०/प्र०ग्रा०पं०/2022-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1027/रा०नि०आ०अनु०-2/4053/2022 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), चम्पावत एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे :-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
21.11.2022 एवं 22.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	23.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	25.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03.12.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	05.12.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

विकास खण्डवार रिक्त पदों/स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों/स्थानों का विवरण (संख्यात्मक)	
		सदस्य ग्राम पंचायत	प्रधान ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1	चम्पावत	60	01
2	लोहाघाट	20	—
3	पाटी	56	—
4	बाराकोट	31	01
योग	04	167	02

2- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक

21.09.2020 के अनुसार, इन उप निर्वाचनों वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

3- कोविड-19 के दृष्टिगत उप निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

संलग्नक:- सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचनों क्षेत्रों का विवरण।

नरेन्द्र सिंह भण्डारी,  
जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(पंचायत), चम्पावत।





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2023 ई0 (फाल्गुन 06, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल के प्रमाण-पत्रों में मेरी पुत्री नाम MARIYAM AMANA व माता का नाम SHABISTA व पिता का नाम MATIULLAH त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम MARIYAM AMNA व माता का नाम SHABISTAN NADIM SABRI व पिता का नाम MATIULLA है। भविष्य में हमें उक्त सही नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मतीउल्ला पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम  
छापपुर शेरअफगनपुर तहसील भगवानपुर जिला  
हरिद्वार। पिन कोड 247661

सूचना

IN MY educational documents my name is mentioned as UMMEED SINGH Whereas in other documents my name is UMED SINGH in future me to be known and recognized by the name of UMED SINGH S/o Late Dhurat Singh.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

UMED SINGH S/o Late Dhurat Singh

Address Village Khadri Khadak Maaf

Shyampur Rishikesh, District

Dehradun Pin 249204

सूचना

मेरी पुत्री रुचि के हाईस्कूल अनुक्रमांक 20056813, वर्ष 2020 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के प्रमाणपत्रों में मेरा नाम श्वेता देवी अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्वेतलाना है। भविष्य में मेरी पुत्री को रुचि पुत्री श्वेतलाना पत्नी धनपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्वेतलाना पत्नी धनपाल सिंह

नि०-पो.ऑ. थापला, कुराण टिहरी गढ़वाल



## कार्यालय नगर पंचायत चौखुटिया, अल्मोड़ा

### सार्वजनिक सूचना

10 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 174/न0प0चौखुटिया/सा0सू0/2022-23-नगर पंचायत चौखुटिया क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (i) 130 (क), (2), 140, 141, 141-क, 141 ख, (1) (2) के साथ पठित नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय, किराये के भवनों व्यवसायिक भवनों पर भवन कर निर्धारण करने हेतु "सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण" उपविधि-2022 तैयार की गई है जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से अन्दर 30 दिवस के लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चौखुटिया के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यावधि के दौरान उपलब्ध करानी होंगी। बाद मियाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

#### "सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि - 2022

##### 1- संक्षिप्त शीर्षनाम और लागू होने की तारीख

(1) यह उपविधि नगर पंचायत चौखुटिया जिला अल्मोड़ा के सम्पूर्ण सीमान्तर्गत स्थित भवनों पर आरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई है जो "सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि - 2022 कहलाएगी।

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

##### 2. परिभाषाएँ - किसी विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में -

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 म्युनिसिपैलटीज एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "नगर का तात्पर्य" नगर पंचायत चौखुटिया से है।

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से है।

(ङ) "अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चौखुटिया से है।

(च) "प्रशासक" का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है।

(छ) "अवर अभियन्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया में कार्यरत अथवा नगर पंचायत हेतु नामित अवर अभियन्ता से है।

(ज) "कर निरीक्षक" का तात्पर्य कर निरीक्षक नगर पंचायत चौखुटिया अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित कर्मचारी से है।

(झ) "कर संग्रहकर्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत में कार्यरत कर संग्रहकर्ता या ऐसे पालिका कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु समय-समय पर अधिकृत किया गया हो।

(ञ) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है।

(ट) "कबर्ड एरिया" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जिस भाग पर भवन निर्मित हैं।

(ठ) "आवासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग भवन स्वामी/अध्यासी/पट्टाधारक आदि द्वारा निवास हेतु किया जा रहा है।

(ड) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो या जिससे आय सृजन हो रही हो।

(च) "खाली भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसका उपयोग किसी भी रूप में यथा - आवासीय/व्यवसायिक/भण्डारण आदि के रूप में लगातार 90 दिन तक ना किया गया हो।

(छ) व्यवसायिक अनुलग्न भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो (कृषि कार्य को छोड़कर)

(ज) "दूरी" का तात्पर्य मोटर मार्ग व भवन के मध्य हवाई दूरी या भूगत दूरी से जो कम हो लागू होगी।

किसी भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण -

3-(1) नगर पंचायत द्वारा सूचना प्रकाशित कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी उपभोगकर्ता से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "क" में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण भर कर प्रत्येक पांच वर्ष में कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "क" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थलों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासिक या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "क" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासक के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "क" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना होगा।



- (5) व्यवसायिक भवन के साथ अनुलग्न भूमि की माप व अनुलग्न भूमि पर कर निर्धारण यदि उसका उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा हो तो उसी प्रकार आरोपित होगा जैसे वह भूमि कोई एक मंजिला भवन है।
- (6) नगर में ऐसे समस्त स्थापित टावर, होडिंग वाले भवन, दूर संचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर, खुले स्थान पर पर प्रतिस्थापित किये गये हों की माप पर भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी।
- (7) नगर स्थित विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजी भूमि पर स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी में माप के अनुसार भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी।

#### 4- सम्पत्तियों का वर्गीकरण -

- (1) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत चौखुटिया द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्ति/भवन की अवस्थिति का वार्षिक वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात् -
- (क) मोटरबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर :-
- (ख) मोटरबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर
- (ग) मोटरबल रोड से 100 मीटर से अधिक तक की दूरी पर

#### (2) अधिशासी अधिकारी उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा -

- (क) पक्का भवन आर0आर0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित या
- (ख) अन्य पक्का भवन, या
- (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।
- (3) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत चौखुटिया तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को 9 विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा -
- (एक) मोटरबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का मकान।
- (दो) मोटरबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 सहित पक्का भवन।
- (तीन) मोटरबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का भवन।
- (चार) मोटरबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (पांच) मोटरबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (छ) मोटरबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (सात) मोटरबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है।
- (आठ) मोटरबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है।
- (नौ) मोटरबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है।
- (नोट - सम्बन्धित भवनों की दूरी भवन के समीप स्थित मोटर मार्ग / जीपेबल मार्ग से हवाई दूरी के आधार पर आंकी जाएगी)

#### 4 - (क) न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण - अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत चौखुटिया वार्ड के भीतर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कबर्ड एरिया की प्रति इकाई (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा -

- (एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर और
- (दो) भवन के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत चौखुटिया ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों की पच्चीस निम्न-निम्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्षिक सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिए आपत्तियां रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जाएगा।



(तीन)- आवासीय भवन का प्रस्तावित सनस्त बाडों के लिए कबर्ड एरिया की मासिक किराया दर प्रति वर्ग फिट/गाह

क्र० सं०	गार्ड का नाम/नम्बर	पक्का भवन आर०सी०सी०/आर०सी०			अन्य कच्चा भवन			कच्चा भवन		
		मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
1	वार्ड-01 (गनाई)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
2	वार्ड-02 (फुलई)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
3	वार्ड-03 (धुधलिया)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
4	वार्ड-04 (चौदीखेत)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10

4.(ख) अनावासिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (4क) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है -

अनुसूची		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	आवासीय भवन का व भाग जो किराये पर दिया हो	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
2	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कामप्लेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल तीन स्टार तक, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पांच गुना
3	प्रत्येक प्रकार के निजी क्लीनिक, पब्लिक क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र या कोचिंग	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
4	कीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
5	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर के चार गुना
6	पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
7	मॉल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्ल, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का छः गुना
8	सामाजिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, बारात घर और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
9	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय (समस्त राजकीय चिकित्सालयों को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
10	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
11	विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजी भूमि पर स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
12	मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थल के ऐसे भवन जिनका उपयोग धर्मशाला, पढ़ाव, मुसाफिरखाना, सराय के लिए होता है, को छोड़ कर अन्य भाग, भवन जिनका उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है या जिस भाग से कोई शुल्क या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता हो।	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का दो गुना
13	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
14	समस्त व्यवसायिक भवन से अनुलग्न भूमि जिसका उपयोग व्यवसायिक भवन के साथ व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है।	भवन के निर्धारित प्रति वर्गफुट के कर के बराबर



4 - (ग) - वार्षिक कर निर्धारण - वार्षिककर का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा -

(एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्यांकन की गणना - सम्पूर्ण भवन का कबर्ड एरिया X 80 प्रतिशत X निर्धारित प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल मासिक किराया की दर X 12=

(दो) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना -

भवन का कबर्ड क्षेत्रफल X अनावासिक भवनों की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर X 12=

(तीन) संदेय कर - ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत वार्षिक सम्पत्ति कर देय होगा।

(चार) संदेय कर का उत्तरदायित्व - भवन स्वामी या अध्यासी या उपभोगकर्ता या पट्टादाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्थानीय निकास द्वारा भवन/भूमि का विवरण/वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र "क" नगर निकाय से प्राप्त कर अपने भवन/प्रष्ठान का पूर्ण विवरण व वार्षिक मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर उपनियम 04 (ग) के अनुसार नगर पालिका को उपलब्ध करायेगा।

(पांच) ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर ग (तीन) के अनुसार नियम संदेय कर को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर होगी।

#### अथवा

कोई कर दाता नियमावली के उपनियम 5 के द्वारा निर्धारित छूट का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा कि वह प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर या उससे पूर्व देय कर को नगर पालिका कोष में जमा कर उक्त तिथि तक रसीद या सूचना प्राप्त कर लेवे।

(5) छूट - आवासिक भवनों के देय कर में छूट अनुमत्य होगी और जो निम्नानुसार होगी।

1. भवन कर वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर तक जमा करने की स्थिति में भवन स्वामी को देय भवन कर पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट आकलित वार्षिक कर पर प्रदान की जायेगी।
2. भवन 20 से 30 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 5 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)
3. भवन 31 से 40 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 10 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)
4. भवन 41 वर्ष से अधिक पुराना होने पर देय कर में 15 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)

प्रतिबन्ध यह है कि -

1. उपरोक्त बिन्दु सं0 2.3.4 पर भवन कर से छूट प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी भवन की आयुगणना व स्वामित्व प्रमाण हेतु निम्न अमिलेख मान्य होगा -

(क) खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टामिलेख, वारिसान प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति

(ख) विहित प्राधिकारी, नगरपालिका या अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति

(ग) भवन का सबसे पुराना विद्युत बिल गृहकर रसीद/पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि जिसमें भवन की आयु की गणना आदि इंगित हो।

1. नगर पालिका अधिनियम - 1916 की धारा 157 के तहत छूट अनुमत्य होगी।

2. भवन स्वामी, अध्यासी उपभोग कर्ता द्वारा भवन कर जमा न करने की स्थिति में भवन कर की वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(6) स्वनिर्धारण - आवासिक भवन के विषय में भवन कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुये नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ इस नियमावली के प्रपत्र "क" में सम्पत्ति कर का विवरण अंकित करते हुए नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक यथा स्थिति प्रपत्र "क" के साथ नगर पंचायत चौखुटिया में धनराशि जमा कर सकेगा।

(7) - कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना -

(1) सभी भवनों की कर निर्धारण सूची गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी -

(क) भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति 'क' में सूचनायें न देने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक/अध्यासी अधिकारी नगर पंचायत या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर,

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे -

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो, का नाम,

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हों, सम्पत्ति का अभिधान,

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है, यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भवन से अनुलग्न समूह के लिए कबर्ड एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।

(पांच) भवन का कबर्ड एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छ) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,



(2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची - ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषयों में प्रपत्र "क" पर और अनावासिक भवनों, जिनके विषय में प्रपत्र पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु भवन नियम 5 -क के उपलब्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(8)- सम्पत्तिकर निर्धारण - किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ पालिका में नगद, पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक खाते में ड्राफ्ट/चैक अथवा नगर सेवा पोर्टल या शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित माध्यम से जमा कर सकता है।

(9) शास्ति (1)- यदि किसी भवन स्वामी, अध्यासी, उपभोगकर्ता द्वारा उपविधि के उपबन्धों के अनुसार स्वकर निर्धारण सम्बन्धी सूचना/कोई तथ्य छिपता है त्रुटि करता है/भवन कर आंगणन में कमी करता है और ऐसा पाये जाने पर त्रुटि/छिपाये गये कर का दो से चार गुना जैसा कि कर निर्धारण समिति निर्धारण करें भवन स्वामी/अध्यासी/उपभोगकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।

(2) - संदेय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक पालिका कोष में जमा न करने पर आगामी वित्तीय वर्ष में संदेय कर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना होगा जो प्रत्येक बकाया वर्ष पर लगातार लागू रहेगा।

(10) स्वामित्व - उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन मात्र पालिका करों की वसूली के प्रयोजनार्थ किया गया है संदेय कर से सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी वाद की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/अध्यासी का होगा।

वी0एस0 कनवासी,  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत, चौखुटिया।

जयवर्धन शर्मा,  
प्रशासक,  
नगर पंचायत, चौखुटिया।

## कार्यालय-नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर

### सार्वजनिक सूचना

02 जुलाई, 2022 ई०

पत्रांक 376/न०पा०प०/उपविधि-प्रकाशन/2020-2021-नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर जनपद टिहरी गढ़वाल, सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 की धारा-298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा 2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा 1 (II)(III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2022" बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन सामान्य एंवम् जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एंवम् सुझाव प्रकाशित की जा रही है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि 14 दिन अर्थात् दो सप्ताह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर को प्रेषित की जा सकेगी।

### अध्याय-23

#### सामान्य

#### 1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, " फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2022" कहलायेगा।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

#### 2- ये उप-नियम नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

#### 1. प्रसंग:

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबन्धन में है। यह महत्वपूर्ण है कि उचित वैज्ञानिक प्रबन्धन इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के श्रोत को प्रदूषित न करें।

#### 1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति:

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के इस फार्मूला प्रकाशित किया है राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और



जीवित बने रहे और अच्छी सफाई बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करने है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

### 1.2 उत्तराखण्ड में प्रबन्धक प्रोटोकॉल:

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश संख्या-10/2005 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये हैं, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एंजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशन्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है। नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम-1976/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबन्धन के लिए तैयार किया है जो कि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या-597/IV(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22 मई, 2017 राज्य का सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकॉल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबन्धन बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकॉल के है कि राज्य शहरी परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

### 2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरण:

सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या-597/IV(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22 मई, 2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत



किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

### 3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है:

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ़दे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
  2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़दे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
  3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
  4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्धन हेतु है।
  5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में सहभागी की सुविधा देना।
4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:
- 4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:
- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहल आये।
  - जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
  - सुरक्षा प्रक्रिया जैसे कि सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- 4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन:
1. फीकल स्लज और ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
  2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे के:
    - अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मापदंड का अनुपालन करेगा।



ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

#### 4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पालिका की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 20 कि०मी० के अन्तर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस०टी०पी० में परिवहन किया जायेगा।

#### 5. सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा गियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकॉल 2017 में वर्णित है।

2. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफटी गियर और यंत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आखों की सुरक्षा जैसे कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोर्वेजर और उनके पुनर्वास नियम-2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गद्दे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्याधिक भार हेतु है या मेन होल का आच्छादन टूटने बचा रहे।

6.1. नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टिक ट्रांसपोर्टर और उसके पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति का भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेगा परिवहन प्रपत्र और परिशिष्ट-ए,2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

#### सारणी 1 पंजीकरण व्यय:-

अ. प्रारम्भिक पंजीकरण	:	रु0-2,000/-प्रति गाडी
ब. नवीनीकरण	:	रु0-1,500/-प्रति गाडी
स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	:	रु0-1,000/-प्रति गाडी
द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	:	रु0-1,000/-प्रति गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा।)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है, नगर पालिका परिषद्, बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अन्तर आ सकता है।

#### 7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र में समस्त मालिका जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गद्दे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका, में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गद्दे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर पालिका, कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर पालिका अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत् है:-



- अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका फंड में जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।
- ब. नगर पालिका किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसके अन्तर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़दे से सम्बन्धित है। एक यादगार सामझदारी नगर पालिका और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहकर्ता के बीच अनुबन्धित होगी। जो यह अधिकतर देगा कि वह इसकी लागत वसूली करे, और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।
- स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम में अन्तर्गत होगा, करना होगा।

क्र0सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गढ़दे के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि है।	निर्धारित समयावधि में खाली न किये जाने पर दण्ड मासिक रूप से।
1.	टीनशैड वाला मकान	4,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	50/-
2.	अन्य समस्त मकान	8,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	100/-
3.	दुकान	8,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	200/-
4.	समस्त सरकारी कार्यालय/संस्थान	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	250/-
5.	निजी कार्यालय	10,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
6.	बैंक	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-

7.	धर्मशाला/आश्रम	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
8.	होटल/गेस्ट हाउस (1-10 बैड वाले)	10,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
9.	होटल/गेस्ट हाउस (10-20 बैड वाले)	15,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	1,500/-
10.	होटल/गेस्ट हाउस (20-30 बैड वाले)	20,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	2,000/-
11.	3 स्टार होटल	25,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	3,500/-
12.	5 स्टार होटल	30,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	5,000/-
13.	सरकारी स्कूल/कालेज/शैक्षणिक संस्थान	8,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
14.	निजी स्कूल/शैक्षणिक संस्थान	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
15.	सरकारी हाँस्पिटल	10,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
16.	प्राइवेट हाँस्पिटल/नर्सिंग होम (1-10 कमरे वाले)	8,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	800/-
17.	प्राइवेट हाँस्पिटल/नर्सिंग होम (10-20 कमरे वाले)	12,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	1,200/-
18.	प्राइवेट हाँस्पिटल/नर्सिंग होम (20-30 कमरे वाले)	15,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	1,500/-
19.	अन्य उद्योग	10,000/-	कम से कम 1 वर्ष में एक बार	1,500/-
20.	2 व्हीलर व्हीकल शो-रूम	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-
21.	पैथोलोजिकल लैब	9,000/-	कम से कम 3 वर्ष में एक बार	1,000/-

नोट:-



1. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी।
2. सैप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने या दूसरे फेरे की स्थिति होने पर दूसरे फेरे में ₹0-1,000/- की छूट दी जायेगी।
8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देगा:
  - 8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर मकान के शौचालय गढ़वे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।
  - 8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त में वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा, और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर में जमा होगी।
  - 8.3 नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्र नगर के अपने क्षेत्र के सैप्टिक टैंक खाली होने का अभिलेख रखेगा।
  - 8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैंक बायोडाइजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

#### 9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाज का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना

#### सारणी 3: दंड

क्र0स0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण मल
1.	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1,000/-	20,000/-	आर0टी0ओ0 द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2.	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5,000/-	10,000/-	

3.	जी०पी०एस० जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5,000/-	10,000/-	
4.	नाली/सडक/खुल क्षेत्र में अवशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन	10,000/-	15,000/-	
5.	आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर अनुपालन	3,000/-	5,000/-	
6.	नगर निकाय/एस०एम०सी० द्वारा सूचित किये गये स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	5,000/-	8,000/-	

सुश्री अमरजीत कौर,  
अधिशारी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्,  
नरेन्द्र नगर, टि०ग०।

राजेन्द्र विक्रम सिंह पंवार,  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद्,  
नरेन्द्र नगर, टि०ग०।



## कार्यालय—नगर निगम, काशीपुर जिला—ऊधमसिंह नगर

### भाग 1: अधिनियम (Regulations)

उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकॉल 2017 के अनुसार

काशीपुर म्युनिशिपल कोर्पोरेशन फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफ.एस.एस.एम.)

एक्ट—2021

29 दिसम्बर, 2022 ई0

पत्रांक 1322/मु0कार्यालय/2022-23—उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—597/IV(2)—श0वि0—2017—50(सा0)16 दिनांक 22 मई, 2017 एवं उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी संबंधित कानूनों के अनुसार नगर निगम, काशीपुर अपने अधिकार-क्षेत्र में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम) सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

#### 1. शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

यह अधिनियम काशीपुर म्युनिशिपल कोर्पोरेशन फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफ.एस.एस.एम) एक्ट -2021" केहलाएगा। ये नगर निगम, काशीपुर की सीमा में प्रभावी होगा। इसे आगे अधिनियम तथा नगर निगम, काशीपुर को निगम लिखा जायेगा। यह अधिनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

#### 2. (क) अधिकार

यह अधिनियम निम्नलिखित प्राविधानों को निगम क्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम बनायेगा।

- उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017
- राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम), 2017
- मैन्युअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, 2013
- मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
- मैन्युअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता-IS Code 2470 Part I & II, 1985, Reaffirmed 1996
- केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- उत्तराखण्ड के पानी और स्वच्छता से संबंधित समस्त राज्य कानून

#### (ख) परिभाषाएं

- फीकल स्लज (मल कीचड़) - यह गड़दे शौचालय, सेप्टिक टैंक, एक्वा प्राइवेट और डाई टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम के तल पर जमा हुआ पदार्थ है, जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है।
- सेप्टेज - सेप्टिक टैंक, सेसपूल, या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस (मैल, स्लज और ग्रीस) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है। इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस, ग्रिट, बात और मलबे के संदूषण होते हैं।
- एफ्लुएंट- सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरने वाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है।
- ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम - स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड़दे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं।
- सेप्टिक टैंक - एक भूमिगत टैंक जो अपशिष्ट जल का उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन और अवायवीय पाचन के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड़दों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है। सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है (जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृत्ति पर)
- डीस्लजिंग- सेप्टिक/इम्हॉफ टैंक, इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज/कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना।
- सीवरेज- शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिसमें मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (मल और मूत्र आदि), भंग या असंगत, होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है।
- सीवरेज सिस्टम - सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहलाता है जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा।



- ix. उपचार- यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आने के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिससे इसका पुनः उपयोग या सुरक्षित निपटान हो सकता है।
- x. सह-उपचार- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर फीकल स्लज और सेप्टेज का सह-उपचार एक उपचार प्रक्रिया है जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फीकल स्लज एंड सेप्टेज को प्राप्त करता है, इसका पूर्व-उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों में वितरित करता है।
- xi. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन- वैक्यूम पंपों से युक्त लीक-प्रूफ टैंकर जो आन साइट सैनेटेशन से फीकल स्लज एंड सेप्टेज के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है।
- xii. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल- निकाय स्तर पर फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित है।

### 3. विषय क्षेत्र

यह अधिनियम की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन में लगे सभी हितधारकों के लिए लागू है - ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (ओ.एस.एस) के स्वामी और उपयोगकर्ता, डीस्लजिंग और सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटर, सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी)- समेत।

यह अधिनियम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त श्रेणी के भवनों पर लागू होगा चाहे सार्वजनिक या निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, प्रस्तावित, नियोजित या मौजूदा आदि।

#### 4.1 निगरानी समिति

निम्नलिखित निगरानी समिति होगी जो सेप्टेज प्रबंधन से सम्बंधित क्रियाओं का आवश्यकतानुसार एवम निश्चित अंतराल पर निगरानी करेगी।

क्रमांक	पदनाम	सदस्य
1.	जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर	अध्यक्ष
2.	मेयर, नगर निगम, काशीपुर	उपाध्यक्ष
3.	नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य
4.	श्रेणीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर	सदस्य
5.	अधीक्षक अभियन्ता, जल निगम, उधमसिंहनगर	सदस्य
6.	अधीक्षक अभियन्ता, जल संस्थान, उधमसिंहनगर	सदस्य
7.	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, काशीपुर	सदस्य
8.	सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य सचिव

#### 4.2 सेप्टेज मैनेजमेंट सेल समिति

Septage Management Cell: State Government by notification shall direct to each urban local body/District Board to create a "Septage Management Cell" (SMC). The cell shall have the following members:

क्रमांक	पदनाम	सदस्य
1.	नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर	अध्यक्ष
2.	सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य
3.	अधिसासी अभियन्ता, पेयजल निगम, काशीपुर	सदस्य
4.	अधिसासी अभियन्ता, जल संस्थान, काशीपुर	सदस्य
5.	श्रेणीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर	सदस्य
6.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य
7.	सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, काशीपुर/प्रभारी सीवरेज प्लांट, काशीपुर	सदस्य
8.	सफाई निरीक्षक, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति इस अधिनियम का अनुपालन, निगरानी एवम् दण्ड सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार रहेगी। इस अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपरोक्त समिति की बैठक समय-समय पर आहूत की जाएगी। प्रत्येक दशा में प्रति वर्ष कम से कम 04 बैठके करायी जानी अनिवार्य होगी। सफाई निरीक्षक, जो सदस्य सचिव हैं, समिति की बैठक बुलाएंगे।

उपरोक्त समिति की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा की जाएगी, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है।

#### 5. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम का निर्माण और रखरखाव

यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढे, बयो-डाइजेस्टर आदि) के निर्माण और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।

- 5.1 नगर निगम, काशीपुर में स्थित घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम के स्वामी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:

##### 5.1.1 सेप्टिक टैंक/ऑनसाइट सैनिटेशन का डिजाइन और निर्माण

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक या अन्य ऑन साइट सैनिटेशन का ठीक से निर्माण एवम् प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) और CPHEEO मैन्युअल, 2013 में उल्लिखित है।



- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑन साइट सैनिटेशन का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव, रिसना, रिसाव या अन्यथा बचने से पर्यावरण को कोई प्रदूषण न हो। इसके लिए ऑन साइट सैनिटेशन की समय-समय पर मरम्मत का काम (repair or retrofitting) मालिक द्वारा किया जाएगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑन साइट सैनिटेशन में छत का पानी, सतह-पानी, रन-ऑफ या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑन साइट सैनिटेशन से अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान सोख गड्ढों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।

#### 5.1.2 ऑन साइट सैनिटेशन का खाली कराना (डीस्लजिंग)

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑन साइट सैनिटेशन को नियमित रूप से खाली कराएँ (तीन साल में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो)।
- स्वामी निगम को सूचित करेंगे, जब सेप्टिक टैंक unit की सफाई करनी है।
- जहाँ स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगे जिनके पास फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सेवाएँ प्रदान करने के लिए निगम द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस हैं।

#### 5.1.3 उपभोक्ता शुल्क का भुगतान

- स्वामी या लाइसेंस-युक्त निजी ऑपरेटरों द्वारा फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि निगम बोर्ड द्वारा तय किया जाता है तथा सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा स्वीकार किया गया है, जो इस अधिनियम में आगे अधिसूचित है।

#### 5.2 निगम के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

- निगम में स्थित सभी ऑन साइट सैनिटेशन (septic tank, pits, biodigester etc) का निगम में पंजीकरण के लिए निगम, एक पंजिका तैयार करेगा। जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि स्वामी का नाम, स्थान (जी0पी0एस0), ऑन साइट सैनिटेशन का प्रकार, आकार और स्थिति, खाली करने की आवृत्ति आदि जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है। इसके लिए निगम सर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।
- सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए ऑन साइट सैनिटेशन के पंजीकरण को अपडेट किया जाएगा। जिला विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण मानचित्रों की अनुमति देते समय ऑन साइट सैनिटेशन पंजीकरण कराने को अनिवार्य शर्त बनायेगा।

#### 5.2.1 ऑन साइट सैनिटेशन का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना

- निगम एवम् जिला विकास प्राधिकरण एवम् उसकी ईकायों द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित किया जायेगा। जब ऑन साइट सैनिटेशन का निर्माण IS Code 2470 भाग I और II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है। यदि उल्लंघन हैं, तो निगम/ जिला विकास प्राधिकरण दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा।
- निगम ऑन साइट सैनिटेशन को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगा।

#### 6 मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन

यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि निगम में स्थित ऑन साइट सैनिटेशन रोकथाम इकाइयों से फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का उचित संग्रह, खालीकरण, उपचार, सुरक्षित निपटान एवं पुनः उपयोग के लिए, इसका निर्धारित साइटों तक सुरक्षित परिवहन हो सके।

#### 6.1 फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के संग्रह और परिवहन में निगम के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

##### 6.1.1 डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण

- निगम अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित पंजीकरण, लाइसेंस एवम् परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा। इसमें निजी-स्वामित्व के साथ-साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं जैसे निगम, जल संस्थान, काशीपुर, जल निगम काशीपुर आदि इसके अलावा यह क्षेत्र के बाहर से आने वाले वाहनों (दोनों निजी और सरकारी) पर लागू होता है।
- निगम डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार-क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस/परमिट प्रदान करेगा। जोकि फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में उल्लिखित और सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस, परमिट दिए जाएंगे जिस हेतु प्रारूप-ख होगा।
- नगर निगम, काशीपुर के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी निगम के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिये अपने उद्भव के निकाय द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हैं। ऐसे वाहनों के प्रवेश की एक लॉग-बुक वाहन में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर रखी जायेगी। नगर निगम, काशीपुर में इन वाहनों के संचालन की शर्तें सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्धारित की जाएंगी।



- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा तय किया गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा मानकों को पूरा करना अनिवार्य हैं।
- निगम क्षेत्र में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर खाली करवाना।
- निगम सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस/जुर्माना जारी करना जो इस अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
- निगम डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परमिट के लिए अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।

- निगम अपनी वेबसाइट और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर समय-समय पर लाइसेंस-प्राप्त/पंजीकृत ऑपरेटरों की सूची को प्रकाशित करेगा।
- निगम प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद सम्बंधित भवन स्वामी को फीडबैक फॉर्म प्रदान करेगा।
- निगम सेप्टेज प्रबंधन की गतिविधि तथा फीडबैक के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग करेगा।
- शेड्यूल्ड डीस्लजिंग- अधिनियम की धारा 5.1.2 में वर्णित समय-अवधि के अनुसार निगम अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित ऑन साइट सैनिटेशन को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम विकसित कर सकता है।

## 6.1.2

**सैप्टेज डीस्लजिंग वाहनों की प्राप्तिकरण और कर्मचारियों की भर्ती**

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट के संग्रह और परिवहन के लिए सैप्टेज डीस्लजिंग वाहन पर्याप्त संख्या में हों। जिसके लिये नगर निगम स्वम् वाहन त्रय कर सकता है। अथवा निविदा आमंत्रित करते हुये निजी ऑपरेटरों का चयन कर सकता है।
- निगम अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल फीकल स्लज एंड सैप्टेज की सुरक्षित संचालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
- अगर निगम निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ निविदाके माध्यम से ले रहा है, तो अनुबंध अवधि अधिकतम १ वर्ष की होगी अथवा प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकरण सशर्त होगा। जोकि ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके राज्य फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में वर्णित और सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा अधिसूचित अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन पर आधारित होगा।

## 6.1.3

**सैप्टेज डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी-**

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सैप्टेज परिवहन वाहन सैप्टेज टैंक/पिट से एकत्र किया गया। फीकल स्लज एंड सैप्टेज केवल सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा चिन्हित स्थलों/उपचार केंद्र पर ही निस्तारण करेंगे।
- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सैप्टेज परिवहन टैंकर (जी0पी0एस0) सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग की जा सकती है। पंजीकृत वाहन स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी की वह जी0पी0एस0 सिस्टम को वाहन पर इस तरह लगायेगा, कि आसानी से बार-बार हटाया न जा सके तथा जी0पी0एस0 को अनवत चालू रखेगा। निगम को बिना सूचना के परिवहन अनाधिकृत की श्रेणी में होगा।
- निगम फीकल स्लज एंड सैप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए ट्रीपलेट डीस्लजिंग प्रमाण पत्र तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति ऑन साइट सैनिटेशन के मालिक को सौंपी जाएगी, दूसरी प्रति निपटान स्थल पर, और तीसरी प्रति निगम कार्यालय में सुरक्षित की जाएगी। जिस पर ऑन साइट सैनिटेशन के मालिक, डीस्लजिंग ऑपरेटर, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और निगम के सहायक/नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।
- निगम भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए ऑन साइट सैनिटेशन मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
- निगम इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरों पद दण्डात्मक कार्यवाही करेगा। दण्ड की व्यवस्थायें तालिका-डी में वर्णित हैं।
- निगम किसी भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगा जो लाइसेंस नवीनीकृत करने में विफलता करे, या इन नियमों या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करे।

## 6.2

**डीस्लजिंग वाहन और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ**

- जो भी व्यक्ति निगम के अधिकार-क्षेत्र में फीकल स्लज एंड सैप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, वह निगम से अपेक्षित लाइसेंस के लिए प्रारूप-ख में आवेदन करेगा।
- आवेदन देने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा अधिसूचित तकनीक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंकर रिसाव-प्रूफ हो, और यांत्रिक डीस्लजिंग उपकरण के साथ युक्त हो इसके अतिरिक्त केवल फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।



- डीस्लजिंग ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय, और नवीनीकरण के समय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पंजीकृत ऑपरेटर समय-समय पर अपने लाइसेंस/परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसा कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा तय किए गए।
- पंजीकृत ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि फीकल स्लज एंड सैप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर निगम द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

## 6.2.1

## दस्तावेजों का रखरखाव

निगम/ठेकेदार/निजी ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए निगम द्वारा प्रदान किए गए डीस्लजिंग प्रमाण पत्र पर फीकल स्लज एंड सैप्टेज के मालिक, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ऑपरेटर, डीस्लजिंग ऑपरेटर, और निगम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये गये तो एवम् जिसकी प्रतिया प्रत्येक को सौंपी जायेगी।

## 6.2.2

## श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालन :

- लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर फीकल स्लज एंड सैप्टेज के केवल यांत्रिक डीस्लजिंग और परिवहन में संलग्न होंगे, और 'मैनुअल स्कैर्वेजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
- पंजीकृत ऑपरेटर अपने सभी कर्मचारी को सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा गियर प्रदान करेंगे।
- पंजीकृत ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि फीकल स्लज एंड सैप्टेज संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से प्रत्येक वर्ष हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और उसकी आख्या के रिकॉर्ड में जमा करें।
- ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित, सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों का बीमा करेंगे।
- सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।
- फीकल स्लज एंड सैप्टेज के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में, ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, और साफ-सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। ऑपरेटर 24 घंटे में निगम के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस-युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

## 6.3

## सैप्टेज मैनेजमेंट सेल के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :-

## 6.3.1 सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना

- सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के क्रियान्वयन एवम् रखरखाव के लिए प्रयुक्त होगा। सैप्टेज मैनेजमेंट सेल यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता पर कोई अनुचित बोझ नहीं है तथा डीस्लजिंग ऑपरेटरों एवम् नगर निगम को कोई अनुचित नुकसान नहीं हो, और फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल निगम को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्ति कर में शामिल करें।
- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क निगम (सुविधा शुल्क), जल संस्थान काशीपुर (संचालन एवम् अनुरक्षण शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्ट (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल संबंधित हितधारकों की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे।

## 6.3.2

## लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना

- लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए सैप्टेज मैनेजमेंट सेल एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क का भुगतान चेक कैश या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर के नाम पर निम्नानुसार होगा:



डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क ( 01 वर्ष के लिए)

- i. प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क: रु 2000 प्रति वाहन
- ii. पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क: रु 1500 प्रति वाहन (जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी)
- iii. विलम्ब शुल्क प्रत्येक 30 दिवस पर रु 500 होगा।

शुल्क संशोधन के अधीन होंगे (अवधि और दर सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा तय किया जाएगा) (सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा तय किया जाएगा और निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा)।

### 6.3.3

#### निगरानी की गतिविधियाँ

- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल, आवश्यकता के अनुसार, सैप्टेज परिवहन वाहनों के लिए निष्पादन मानकों को जारी करेगा।
- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल निगम में चलने वाले सैप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
- यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता है, तो सैप्टेज मैनेजमेंट सेल निगम को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को निम्न तालिका के अनुसार परिभाषित करेगा।

तालिका-D

	Category	Fine in Rs.
निगम में पंजीकृत वाहन	प्रथम बार उल्लंघन करने पर	1000
	द्वितीय बार उल्लंघन करने पर	2500
	तृतीय बार उल्लंघन करने पर	5000 अथवा पंजीकरण का निरस्तीकरण अथवा दोनों
	चतुर्थ बार उल्लंघन करने पर	पंजीकरण का निरस्त
निगम में अपंजीकृत वाहन	प्रथम बार उल्लंघन करने पर	5000
	द्वितीय बार उल्लंघन करने पर	10000 टैकर की जवती

- सैप्टेज मैनेजमेंट सेल फीकल स्लज एंड सैप्टेज सेवाओं से संबंधित शिकायतें ऑन साइट सैनिटेशन के मालिकों, डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी। यदि आवश्यक हो, सैप्टेज मैनेजमेंट सेल अपीलीय निकाय या शिकायत निवारण क्रियाविधि बना सकते हैं।

## 7

### फीकल स्लज एंड सैप्टेज का उपचार और पुनःउपयोग/ निपटान

#### 7.1 डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सेप्टिक टैंक/पिट से एकत्र किया गया फीकल स्लज एंड सैप्टेज, केवल नजदीकी सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार कर निपटाया जाएगा।
- डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट-युक्त फीकल स्लज एंड सैप्टेज का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।

#### 7.2 उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ :

- उपचार केन्द्र के ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास निगम द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
- उपचार केन्द्र के प्रबंधक निगम द्वारा जारी किए गए फीकल स्लज एंड सैप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड डीस्लजिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
- उपचार केन्द्र के संचालक फीकल स्लज एंड सैप्टेज के निपटान के लिए टिपिंग शुल्क के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
- उपचार केन्द्र सैप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएगी। तथा उपचार के बाद निस्तारित स्लज और अपशिष्ट जल को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार बाहर भेजेगी। इसके लिये समय-समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा।
- उपचार अंतिम उत्पाद (उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित) का अधिकतम पुनः उपयोग, मानकों और मानदंडों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योग बिजली संयंत्र, सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न पुनः उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी/जल में डाला जाएगा।
- फीकल स्लज एंड सैप्टेज के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँ: यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार या फीकल स्लज एंड सैप्टेज की अवांछनीय गुणवत्ता के कारण उपचार केन्द्र फीकल स्लज एंड सैप्टेज को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो उपचार केन्द्र संचालक को सैप्टेज परिवहन ऑपरेटर को संबंधित कर्मियों को हस्ताक्षर के साथ अस्वीकृति का कारण लिखित में देना होगा। इस स्थिति में, सैप्टेज परिवहन ऑपरेटर द्वारा सैप्टेज को सैप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।



## 7.3 निगम के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

- निगम, उत्तराखण्ड पेयजल निगम काशीपुर के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में सैप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारीक संरचना तैयार करायेंगे।
- निगम उपचारित फीकल स्लज एंड सैप्टेज तथा पानी के पुनः उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिए, इसे किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा।

## 8 प्रचार- प्रसार गतिविधियाँ

निगम फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित प्रचार- प्रसार और क्षमता निर्माण गतिविधियों का कार्य करेगा:

- ऑन साइट सैनिटेशन मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से ऑन साइट सैनिटेशन का डिजाइन, निर्माण तकनीक, इसके आकार आदि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार- प्रसार को बढ़ावा देना।
- फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सीवरों और सैप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP (MoHUA 2018) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

## संचालन के नियम और शर्तें -

1. लाइसेंसधारी काशीपुर म्युनिशिपल कोर्पोरेशन फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट (एफ.एस.एस.एम) एक्ट-2021 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
2. लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि issuing Authority/SMC द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सके।
3. लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा, जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
4. लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन करेगा।
5. लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा। कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। असाधारण स्थितियों में, यह केवल अपेक्षित सावधानियों, सुरक्षा उपकरणों और निगम की अनुमति के साथ किया जा सकता है।
6. यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नहीं है।
7. निगम इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय-समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है।
8. लाइसेंसधारी ऑपरेटर को निगम द्वारा निर्देशित सैप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान की पर्याप्त और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है।
9. लाइसेंसधारी निगम की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैंकों की जीपीएस ट्रैकिंग स्थापित करना। उसके एक्सेस राइट्स निगम द्वारा स्वयं प्रयोग किये जायेंगे अथवा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक किया जा सके।
10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सैप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ले जाया जाएगा जो निगम द्वारा निर्दिष्ट हैं।
11. फीकल स्लज एंड सैप्टेज का परिवहन, सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए, निगम द्वारा निर्धारित मार्गों एवम् समय में किया जाएगा।
12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सैप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।

अनुबंध E - नगर निगम काशीपुर में डीस्लजिंग और सैप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क की सूची<sup>1</sup>

Sr. no.	CATEGORY	Charges (Per trip upto 3000 Litres)	Period of Interval for Desludging of Septic tank (As per Schedule time given below or when tank becomes Two third filled whichever is Earlier)
1	Kuccha house/Hut	500.00	02 years (It will be done by Nagar Nigam Vehicle)
2	Tin shed type house	1000.00	02 years (It will be done by Nagar Nigam Vehicle)
3	All Other house (Pucca House)	2000.00	02 years
4	Shop	2000.00	02 years
5	All Govt/ Private Offices	2500.00	02 years



6	Bank	3000.00	01 year
7	Community Toilet/Public Toilet	1000.00	01 year
8	Restaurant	2500.00	01 year
9	Hotel /Guest house 01 to 10 Room	2000.00	01 year
10	Hotel /Guest house 11 to 20 Rooms	2500.00	01 year
11	Hotel /Guest house above 20 Rooms	4000.00	01 year
12	Dharamshala 01 to 25 Rooms	1500.00	01 year
13	Dharamshala above 25 Rooms	2000.00	01 year
14	3-Star hotel	3000.00	01 year
15	5-Star hotel	4000.00	01 year
16	Govt. School/College (Upto 1000 Students)	1000.00	01 year
17	Govt. School/ College (Above 1000 Students)	1500.00	01 year
18	Private school/ College (Upto 1000 Students)	2000.00	01 year
19	Private school/ College (Above 1000 Students)	3000.00	01 year
20	2 wheeler vehicle showroom (Without Service Centre)	2000.00	01 year
21	2 wheeler vehicle showroom (With Service Centre)	3000.00	01 year
22	4 wheeler vehicle showroom (Without Service Centre)	3000.00	01 year
23	4 wheeler vehicle showroom (With Service Centre)	4000.00	01 year
24	Multiplex	3000.00	01 year
25	Hostel 01 to 10 Rooms	1800.00	01 year
26	Hostel 11 to 20 Rooms	2200.00	01 year
27	Hostel 21 to 50 Rooms	2500.00	01 year
28	Hostel above 50 Rooms	3000.00	01 year
29	Marriage hall / Banquet hall	2500.00	01 year
30	Bar	2500.00	01 year
31	Govt. Hospital (Upto 20 Bed)	2000.00	01 year
32	Govt. Hospital (Above 20 Bed)	2500.00	01 year
33	Nursing home/Clinic (Upto 20 Bed)	2000.00	01 year
34	Nursing home/Clinic (Above 20 Bed)	3000.00	01 year
35	Pathological lab	1500.00	01 year
36	Private hospital upto 20 bed	2500.00	01 year
37	Private hospital 21-50 bed	3000.00	01 year
38	Private hospital above 50 bed	4000.00	05 Months
39	Rice mill/other mill	2500.00	01 year

नोट: उपभोक्ता शुल्क संशोधन के अधीन होगा। प्रत्येक अतिरिक्त ५०० लीटर के लिये उपरोक्त शुल्क में १५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि होगी।

यूजर चार्ज- उपभोक्ताओं से लिये गये यूजर चार्ज निगम एवम् सैप्टेज ट्रान्सपोर्ट के मध्य निम्नानुसार विभाजित किया गया है।

Sr. No	Category According to USER CHARGES per trip	Registered Desludging Vehicle Owner's Share	Nagar Nigam KASHIPUR Share
1	2	3	4
1	Upto Rs. 2000	80%	20%
2	Rs. 2001-3000	75%	25%
3	Rs. 3001-4000	70%	30%
4	Above Rs. 4000	65%	35%

b) सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणदायी संस्था पेयजल निगम (अमरत), काशीपुर हैं तथा कार्यदायी संस्था के अनुसार प्लांट ३१ मार्च २०२२ में पूर्णत रूप से संचालित होगा।

विवेक राय,  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, काशीपुर।

उषा चौधरी,  
महापौर,  
नगर निगम, काशीपुर।

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०८ हिन्दी गजट/४५-भाग ८-२०२३ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।